

रीवा, सतना एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

: वीफ बॉक्स :

सोशल मीडिया

अकाउंट बनाने के लिए

18 की उम्र जरूरी



नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट को लेकर कानून बनाने पर विचार करने को कहा।

कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करना होगा। नाबालिग 18 साल से कम उम्र के होते हैं और खुद कानूनी अनुबंध नहीं कर सकते।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस (JURCA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा की मांग की गई है।

पीओके के लोग बोले-

हमें भारत का रास्ता दो,

तारबंदी हटाओ



नई दिल्ली, एजेंसी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आजादी की आवाजें तेज हो गई हैं। रुष्ट (निबंधन रेखा) से लगभग 7 किमी दूर मंधोल में 25 हजार लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम भारत से मिलना चाहते हैं।

पाक पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। जॉइंट अवामी लीग (JAL) के नेताओं ने ऐलान किया है कि पाक सरकार को पुंछ और मेहर का रास्ता खोलना होगा। ये रास्ता भारत की ओर जाता है। पांच जून से PoK में जारी आंदोलन के 115वें दिन सोमवार की मंधोल के इलाके में खासी गहमागहमी रही। ऋष्य के मुजफ्फराबाद से लोग एलओसी के पास जुटने लगे। एलओसी पर लोगों का हुजूम रोज बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान ने बरसों तक उनके हकों को दबाया है, लेकिन अब इंतहा हो चुकी है। फैसला होकर रहेगा।

राहुल गांधी 1 अक्टूबर को

म.प्र. के बालाघाट जाएंगे



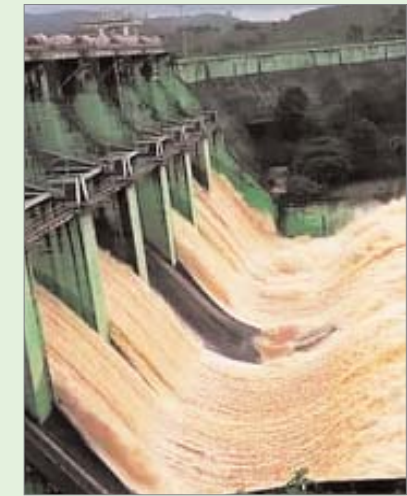
भोपाल, एजेंसी। मध्यप्रदेश के बालाघाट में बैगा आदिवासी बच्चों की मौतों के बीच राहुल गांधी 1 अक्टूबर को बालाघाट आएंगे। वे बेहर और बिरसा के प्रभावित आदिवासी इलाकों में जाकर मृत बच्चों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। बालाघाट में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 32 बच्चों की मौत हो चुकी है।

राहुल गांधी का 13 दिन में मध्यप्रदेश में यह दूसरा दौर होगा। इससे पहले वे 19 सितंबर को इंदौर आए थे। यहां उन्होंने 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कार्यक्रम से पहले उन्होंने लिखा था- 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की बीमारी, कुपोषण मौतें हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई सुस्त रही। सरकार सोती रही।

राहुल गांधी ने कहा था- मुख्यमंत्री जी, दीये जलाने और उत्सव मनाने से पुस्तें मिल गई हो तो जरा राज्य की जमीनी हालत भी देखिए। बीमारी, पोषण और साफ पानी की कमी है। चरमपंती स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण छोटे बच्चों की जान जा रही है।

छत्तीसगढ़-इंद्रावती के जलस्तर का 53 साल का रिकॉर्ड टूटा

● नाव-हेलिकॉप्टर से 833 को बचाया ● राजस्थान में ओले, यूपी में जनवरी जैसा कोहरा



नई दिल्ली, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती बस्तर की इंद्रावती नदी का जलस्तर 12.39इ तूफान अनंभ के असर से भारी बारिश के बाद पहुंच गया। यह 53 साल का रिकॉर्ड है और 9

3000 वाली कैंसर दवाई 27 हजार में क्यों बेच रहे

सुप्रीम कोर्ट का दवाओं की एमआरपी पर सरकार

से सवालरिटेलर कीमत से 16% से ज्यादा दाम

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से पूछा कि दवाओं की MRP, 7%, रिटेलर कीमत से 16% से ज्यादा क्यों होनी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच दवाओं की कीमत, जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल डिवाइस के नियंत्रण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

बेंच ने कहा कि करीब 3,000 रुपए की रिटेलर कीमत वाली कैंसर दवा की MRP



लगभग 27,000 रुपए है। कोर्ट ने दवाओं पर एक समान नियम लागू करने की संभावना पर सवाल उठाया। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

याचिकाओं में दवाओं की कीमतों में भारी अंतर से मरीजों और सरकारी योजनाओं पर पड़ने वाले बोझ का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने पिछली सुनवाइयों में उठाई गई चिंताओं का भी जिक्र किया। इनमें दवाओं पर दस गुना या उससे ज्यादा मुनाफे का आरोप शामिल है। बेंच ने दवाओं के मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 के तहत जरूरी और गैर-जरूरी दवाओं के बीच अंतर पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि कॉरपोरेट

कैंसर दवा की कीमत पर सवाल... जस्टिस संदीप मेहता ने कीमतों में बड़े अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, 'बस इस बड़े अंतर को देखिए।

अस्पताल अक्सर मरीजों को अपनी इन-हाउस फार्मसी से दवा खरीदने के लिए कहते हैं। आयुष्मान भारत या अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में इलाज होने पर इसका बढ़ा हुआ खर्च आखिरकार करदाताओं को उठाना पड़ता है।

यूके में सस्टेनेबिलिटी के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बने अनंत अंबानी

छात्रों को ग्रीन एनर्जी पढ़ाएंगे; 2035 तक नेट कार्बन जीरो का रोडमैप तैयार कर रहे

मुंबई, एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को सस्टेनेबिलिटी का प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किया है। यह नियुक्ति औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, ग्रीन एनर्जी और पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में उनके काम को मान्यता देती है। वे छात्रों को ग्रीन एनर्जी के बारे में पढ़ाएंगे।



अनंत रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े काम देख रहे हैं। वे कंपनी को 2035 तक नेट कार्बन जीरो बनाने के रोडमैप पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक ऐसी अकादमिक पदवी है, जो अनुभवी प्रोफेशनल्स और ऑपरेशनल लीडर्स के लिए होती है। पारंपरिक अकादमिक पदों के विपरीत, इसके लिए डॉक्टरेट, पीएचडी प्रकाशन या रिसर्च टेबल की जरूरत नहीं होती।

ऑक्सफोर्ड सैद, वार्विक, क्रैनफील्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के जरिए कॉरपोरेट लीडर्स और प्रोफेशनल्स को अकादमिक क्षेत्र से जोड़ा गया है।

बेहतर जीवन की तलाश में 72 फीसदी प्रवासी मजदूर

कर रहे दक्षिण भारत का रुख, सर्वे में खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी। दक्षिण भारत के तीन बड़े राज्यों में काम करने वाले लगभग 72 प्रतिशत प्रवासी मजदूरों का मानना है कि घर से दूर आकर काम करने से उनके रहन-सहन और जीवन के स्तर में अच्छा सुधार हुआ है। यही कारण है कि इनमें से 57% से ज्यादा मजदूर उसी राज्य में रहकर आगे भी काम करना चाहते हैं।

हालांकि, उनका जीवन पहले से बेहतर तो हुआ है, लेकिन कानूनी और सामाजिक सुरक्षा के मामले में हालात अब भी चिंताजनक हैं। 86 प्रतिशत से भी ज्यादा मजदूरों के पास काम करने का कोई लिखित समझौता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके साथ ही, उन्हें भाषा की



दिवक्त, समाज से जुड़ाव न हो पाने और सरकारी योजनाओं का फायदा न मिल पाने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यह अध्ययन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट (IIMAD) द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के सहयोग से 1824 प्रवासी मजदूरों पर किया गया, जिसमें कर्नाटक, केरल और

क्या है पलायन का मुख्य कारण? साउथ इंडिया इंटरस्टेट माइग्रेशन सर्वे (SIIMS) 2026 के अनुसार, गृह राज्यों में आजीविका की असुरक्षा और रोजगार के सीमित अवसर ही पलायन की सबसे बड़ी वजह हैं। अधिकांश कामगारों ने अपने गृह क्षेत्र में मिलने वाली कम मजदूरी, नौकरियों का अभाव, अनियमित काम, गरीबी और भारी कर्ज को घर छोड़ने का मुख्य कारण बताया।

तमिलनाडु में काम कर रहे श्रमिकों के जीवन और कामकाज के तौर-तरीकों का विश्लेषण किया गया है।

तेलंगाना सीएम बोले- राम अमीरों और शिव गरीबों के भगवान

भाजपा ने राम को चुराया, इसलिए कांग्रेस दक्षिण में सफल और उत्तर भारत में पिछड़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि शिव गरीबों और राम अमीरों के भगवान हैं। उन्होंने भाजपा को अमीरों की पार्टी भी बताया। कहा कि भाजपा ने भगवान राम को अपने राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ लिया है। भाजपा ने राम को चुरा लिया है। सोमवार को दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन के दौरान उनसे पूछा गया कि कांग्रेस दक्षिण भारत में मजबूत है, लेकिन उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत में उसका प्रदर्शन उतना अच्छा क्यों नहीं रहा। रेवंत ने इसकी वजह धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बताई। उन्होंने कहा कि हम द्रविड़ हैं, जबकि उत्तर भारत के लोग आर्य हैं। हम शिव के भक्त हैं और आर्य भगवान राम के भक्त हैं।



कुमार ने कहा- तेलंगाना के सीएम के तौर पर रेवंत रेड्डी को बेहतर पता होना चाहिए। तेलंगाना में वेमुलावाड़ा में दक्षिण काशी और भद्राचलम में दक्षिण

केंद्रीय मंत्री बोले- रेड्डी भगवान को नहीं बंटें... रेवंत रेड्डी के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री बदी संजय कुमार ने कहा कि रेड्डी पहले 'मुस्लिम कांग्रेस' है, कांग्रेस मुस्लिम है' कह चुके हैं। अब वे भगवान राम और भगवान शिव के बीच राजनीतिक सीमाएं खींच रहे हैं।

अयोध्या है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को भगवान राम और भगवान शिव को उत्तर और दक्षिण में नहीं बांटना चाहिए। पीएम मोदी लोकसभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके मुताबिक, काशी विश्वनाथ वाराणसी के आध्यात्मिक केंद्र में स्थित है।

आयोग और सरकार के खिलाफ रणनीति पर कांग्रेस की बैठक

खड़गे बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त

सरकार की कठपुतली, उन्हें हटाएं

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कथित अनियमितताओं के कारण तुरंत हटाने की मांग की और चुनाव आयोग प्रमुख पर दबाव डालने के लिए नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की। कांग्रेस वर्किंग कमिटी की एक अहम बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'देश भर में यह सर्वोच्च है कि उनके निरंतर प्रयास सत्ताधारी पार्टी को लाभ



पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए हैं। इन परिस्थितियों में उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल पद से हटा दिया जाना चाहिए। ' कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने

कहा, 'मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी सरकार की कठपुतली बन गए हैं। यहां तक कि उनके अपने सहयोगी भी उन पर भरोसा नहीं करते। युवा सवाल उठाए और उन्हें पद से हटा देंगे। '

एसआईआर पर आज I.N.D.I.A.

ब्लॉक की बैठक

● अखिलेश नहीं आएंगे: उद्धव गॉनलाइन जुड़ेंगे ● 3 साल में 8वीं, इस साल दूसरी बार जुटेंगे विपक्षी दल

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में आज विपक्षी दलों के I.N.D.I.A. ब्लॉक की बैठक होगी। इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी स्ट्रक्चर और चुनाव आयोग के भीतर सामने आए मतभेदों को लेकर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह पार्टी का दूसरा नेता पहुंचेगा। वहीं शिवसेना (UBT) प्रमुख

उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पार्टी सांसद संजय राजन ने बताया कि पार्टी 2 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन की तैयारी में व्यस्त है। शिवसेना (UBT) दफ्तर के CJP प्रदर्शन का भी समर्थन करेगी। I.N.D.I.A. ब्लॉक की पिछले 3 सालों के दौरान यह 8वीं बैठक होगी। वहीं इस साल की दूसरी बैठक होगी।

एसआईआर में स्थानीय अफसरों

को ज्यादा अधिकार मिलें

मुंबई, एजेंसी। चुनाव आयोग के पोर्टल ECINet में स्थानीय चुनाव अधिकारियों के अधिकारों को लेकर उठे सवालों के बीच महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम का 24 सितंबर को लिखा लेटर मंगलवार को सामने आया। चोकलिंगम ने इसमें वोटर रिकॉर्ड की गड़बड़ियों से जुड़े मामलों में ERO को ज्यादा अधिकार देने और सॉफ्टवेयर में 4 बदलाव की मांग की थी। उनका कहना था कि किसी वोटर के रिकॉर्ड में गड़बड़ मिलने पर हर मामले



में एक जैसी प्रक्रिया लागू नहीं होनी चाहिए। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी श्वश्रू को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि किस वोटर को सुनवाई के लिए बुलाना है, कौन से दस्तावेज लेंगे हैं और किन मामलों को अपने स्तर पर निपटारा जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

‘पिता के बनाए घर में बेटे-बहू का हक नहीं’

13 साल पुराने मामले में अहमदाबाद की सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला



अहमदाबाद, एजेंसी। अहमदाबाद के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने ही बेटे और बहू के खिलाफ 2013 में मुकदमा दायर किया था। इस मामले में अब फैसला 13 साल बाद बुजुर्ग व्यक्ति के पक्ष में आया है। 13 साल की कानूनी लड़ाई के बाद बुजुर्ग व्यक्ति को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपनी कमाई से बनाए हुए घर से अपने बेटे-बहू को निकाल सकता है। शहर की सिविल कोर्ट ने जोड़े को घर खाली करने के लिए 90 दिन का समय दिया है। बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे और बहू की शादी 2002 में हुई थी। वे घर के ग्रांड फ्लोर पर रहते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति पहली मंजिल पर रहते हैं। बहू के साथ में उसकी बेटी भी रहती है। पति-पत्नी के बीच झगड़ों के कारण वे अलग-अलग कमरों में रहने लगे, जिसके बाद बेटे ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। बुजुर्ग व्यक्ति ने बेटे-बहू के झगड़ों से तंग आकर 2013 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत से बेटे-बहू को घर से निकालने का अधिकार मांगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुकदमा दाखिल करते वक्त बताया कि उन्होंने यह प्रॉपर्टी 1980 के दशक में अपनी खुद की कमाई से खरीदी थी और वे ही इसके एकाग्र मालिक हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने दावा किया कि बार-बार कहने के बावजूद, उनके बेटे और बहू ने घर खाली करने से इनकार कर दिया और प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जताया। बुजुर्ग के बेटे ने मुकदमा का विरोध नहीं किया, लेकिन बहू ने आरोप लगाया कि यह मामला उसके पति की मिलीभगत से दायर किया गया था ताकि उनके चल रहे वैवाहिक विवाद के संबंध में उस पर दबाव बनाया जा सके। बहू ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति तलाक चाहता था क्योंकि उसका किसी दूसरी महिला के साथ संबंध था। यह तर्क देते हुए कि यह घर उसका वैवाहिक घर है, उसने वहां रहने का अधिकार जताया क्योंकि यह एक 'साझा घर' था। बहू ने कोर्ट से कहा कि वह अपनी बेटी के साथ एक कमरे में रह रही है और छुट्टे के लिए के प्राधुनानों के तहत उसे घर से नहीं निकाला जा सकता।

वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. बी. एल. जैन को मिला राष्ट्रीय सम्मान
एलजी, अस्थमा और इम्यूनोलॉजी में फेलोशिप से नवाजे गए

जयपुर। राजस्थान के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट तथा मानसरोवर हॉस्पिटल, जयपुर के निदेशक एवं चेयरमैन डॉ. बी. एल. जैन को एलजी, अस्थमा एवं इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और दीर्घकालीन योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें इंदौर में आयोजित ‘आईसीएआईआई कॉन-2026’ (ICAAICON-2026) सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। ‘दी इंडियन कॉलेज ऑफ एलजी, अस्थमा एंड एल्लाइट इम्यूनोलॉजी’ (ICAAI) द्वारा डॉ. बाबू लाल जैन को ‘फेलो ऑफ द इंडियन कॉलेज ऑफ एलजी, अस्थमा एंड एल्लाइट इम्यूनोलॉजी’ (Fellow of ICAAI) की फेलोशिप से नवाजा गया है। संस्था द्वारा दी गई यह उपाधि एलजी, दमा (अस्थमा) एवं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में डॉ. जैन के चार दशकों से अधिक के उल्लेखनीय चिकित्सकीय अनुभव, शोध और विशेषज्ञता को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी मान्यता प्रदान करती है। डॉ. जैन राजस्थान में श्वसन रोगों के उपचार के क्षेत्र में एक अग्रणी और प्रतिष्ठित नाम हैं।

थप्पड़ विवाद : सड़क की गुणवत्ता से शुरू हुआ मामला थाने से प्रदर्शन तक पहुंचा

क्यों आमने-सामने आए आप-बीजेपी

नई दिल्ली, एजेंसी। तिलक नगर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच के दौरान रविवार को हुए विवाद के बाद सोमवार को मामला सड़क से थाने और फिर सियासी प्रदर्शन तक पहुंच गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा पर आप कार्यकर्ता साहिब सिंह को थप्पड़ मारने के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) ने लगातार दूसरे दिन मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की लेकर प्रदर्शन किया। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और तिलक नगर विधायक जर्नेल सिंह कार्यकर्ताओं के साथ विकासपुरी थाने की ओर रवाना



हुए। पुलिस ने थाने से करीब 100 मीटर पहले अग्रसेन भवन रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद आप नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इससे पहले आप

का आरोप लगाते हुए प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केजरीवाल के पहुंचने से पहले ही आउटर रिंग रोड के उक्त हिस्से को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर घेर दिया था। वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। केजरीवाल करीब पांच मिनट मौके पर रुकने के बाद वहां से चले गए। गौरतलब है कि रविवार को करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनी

सड़क की गुणवत्ता जांचने के दौरान प्रवेश वर्मा और जर्नेल सिंह आमने-सामने आ गए थे। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि कि मौके पर मौजूद आप कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार के खिलाफ अपशब्द कहे और काम में बाधा डाली। उन्होंने जर्नेल सिंह पर पीडब्ल्यूडी के काम में कमीशन मांगने का भी आरोप लगाया है।

सोमवार तक मिलीं 5 शिकायतें

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोमवार तक विवाद से संबंधित पांच शिकायतें मिली थीं। इनमें साहिब सिंह की एक, पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की ओर से जर्नेल सिंह व अन्य के खिलाफ दो और बाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से दो शिकायतें शामिल हैं। शिकायतें विकासपुरी और तिलक नगर थानों में दी गई हैं। देर शाम तक किसी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। इंटरनेट मीडिया पर भी दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी रहा।

लाल ग्रह को समझने की कवायद 2028 तक मंगल का नया भूगर्भीय नक्शा बनाएगा चीन, एआई बताएगा अरबों साल पुराना इतिहास



बीजिंग, एजेंसी। चीन 2028 के अंत तक मंगल का नई पीढ़ी का भूगर्भीय नक्शा तैयार करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य लाल ग्रह के अरबों साल पुराने जल और जलवायु इतिहास को समझना है। इसके साथ ही चीन मंगल के भूगर्भीय इतिहास को अलग-अलग कालखंडों में बांटने के लिए अपनी वैज्ञानिक प्रणाली भी विकसित करेगा। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीनी विज्ञान अकादमी के शिक्षाविद और तियांगवेन-3 मंगल नमूना वापसी मिशन के मुख्य वैज्ञानिक हौ जेंग्ल्येन ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने यह बात चीनी भूवैज्ञानिक विज्ञान अकादमी के भूविज्ञान संस्थान में आयोजित एक संगोष्ठी में कही। झुरोंग रोवर ने दिए मंगल के पानी के संकेतचीन का झुरोंग रोवर 2021 में तियांगवेन-1 मिशन के तहत मंगल की सतह पर उतरा था। इससे मिले आंकड़ों ने मंगल के प्राचीन जल इतिहास को समझने में नई जानकारी दी है। चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले तक एक विशाल प्राचीन महासागर मौजूद रहा हो सकता है। इसके अलावा करीब 1.6 अरब साल पहले अल्प अवधि की बाढ़ आने के संकेत भी मिले हैं। इन संकेतों को मंगल की जलवायु के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए भूगर्भीय नक्शे में इन निष्कर्षों की भी शामिल किया जाएगा।

मंगल के इतिहास को नए तरीके से बांटेगा चीन: फिलहाल मंगल के भूगर्भीय इतिहास को मुख्य रूप से तीन बड़े कालखंडों में बांटा जाता है नोआकियन, हेस्पेरियन और अमेजोनियन। इन कालखंडों की पहचान मुख्य रूप से मंगल की सतह पर दिखाई देने वाले उल्कापिंडों के गड्ढों की संख्या और उनकी घनत्व के आधार पर की गई है।

लखनऊ, एजेंसी। बिजली उपभोक्ताओं को अक्टूबर में भी बिजली के बिल से राहत मिलती दिख रही है। जून में 10 प्रतिशत ज्यादा बिजली का बिल देने वाले उपभोक्ताओं का जुलाई में 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में रिकॉर्ड 7.93 प्रतिशत के बाद अब अक्टूबर में भी पांच प्रतिशत से अधिक बिल कम हो सकता है। एफपीपीसीए (ईंधन एवं बिजली खरीद लागत समायेजन) के तहत जुलाई माह के ईंधन अधिभार शुल्क (फ्यूल सरचार्ज) में कमी को देखते



हुए सितंबर के बिजली बिल पर अक्टूबर में सभी श्रेणियों के लगभग 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा जल्द ही आदेश जारी करने की कवायद की जा रही है। जून में भारी-भरकम 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क वसूलने पर विद्युत नियामक आयोग के कड़े रुख के बाद से लगातार

चौथे माह उपभोक्ताओं को बिजली के बिल से कुछ राहत मिलना तय है। गौरतलब है कि कारपोरेशन द्वारा पुराने भुगतान को भी अधिभार में शामिल करते हुए 1610 करोड़ रुपये के लिए जून में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूला गया था। जून में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत वसूलने के बाद कॉर्पोरेशन प्रबंधन जुलाई में भी 10 प्रतिशत वसूलता उससे पहले ही आयोग ने पुराने भुगतान को अधिभार में शामिल करने पर नाराजगी जताते हुए उसे गलत ठहराते हुए आदेश जारी किया था। आयोग ने कहा

था कि वास्तविक बिजली खरीद की लागत एवं ट्रांसमिशन शुल्क के आधार पर ही अधिभार तय होगा। इसमें किसी अन्य माह की देनदारी के भुगतान या समायोजन का शामिल नहीं किया जा सकता। यही कारण रहा कि जुलाई से लगातार उपभोक्ताओं को बिजली का कम ही बिल देना पड़ रहा है। उग्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि एफपीपीसीए गणना में अब पारदर्शिता के चलते उपभोक्ताओं को कानूनन इसका लाभ समय पर मिल रहा है।

घर से बाहर खींचा और पेड़ से बांधा तेलंगाना में काला जादू के नाम पर 60 साल की महिला के साथ मारपीट



हमला: जब उनके पति पल्लाती पोचैया और बेटे पल्लाती महेश ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी कथित तौर पर हमला किया गया। हमलावरों पर महेश की कार का पिछला शीशा तोड़ने का

भी आरोप है। इस घटना के बाद मंचल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 14 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज: इब्राहिमपट्टनम के एसपी केवीएम राजू ने बताया कि हमले के दौरान महिला को नीम के पेड़ से बांध दिया गया था। एसपी ने कहा, ‘पृच्छाछ के लिए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। इस घटना के सिलसिले में कुल 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कथित हमला इस शक और अफवाह की वजह से हुआ कि वेंकटम्मा काला जादू करती थीं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति या समूह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता और अधंशवास या बिना सबूत के लगाए गए आरोपों के आधार पर हिंसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मादुरो को हटाते ही वेनेजुएला ट्रंप के लिए सोने की खान, 20प्रतिशत कट से स्थानीय गैंग्स की भी मौज

वाशिंगटन, एजेंसी। इसी वर्ष मार्च की शुरुआत में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करने की अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे, तब व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में एक बेहद गोपनीय बैठक हुई। इसमें अमेरिकी इंटीरियर सेक्रेटरी डग बर्गम के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कर्पोरेट ट्रेडिंग कंपनियों में शुमार ट्रेफिगुरा के सीईओ रिचर्ड होल्डम पहुंचे थे। उनके हाथ में एक अजीबो-गरीब तोहफा था, वेनेजुएला से लाई गई सोने की 10 चमचमाती सिल्लियां। ट्रंप ने कभी यह कहकर इस सोने को प्रतिबंधित कर दिया था कि यह पर्यावरण को जहरीला बनाता है, लोगों का खून चूसता है और अपराधियों व भ्रष्ट सैन्य अफसरों की जेब भरता है। लेकिन अब मादुरो के हटते ही यह अमेरिकी की नई



विदेश नीति का सबसे बड़ा खजाना बन गया। उसी दिन ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की सरकारी खनन कंपनी मिनरवेन (जिसे अमेरिका खुद कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए

खतरा घोषित कर चुका था) से सोना आयात करने की विशेष छूट दे दी। लेकिन ट्रंप के इस गोल्ड रश के पीछे खोफनाक दलदल है। अमेरिकी कंपनियों द्वारा निकाला जा रहा यह

सोना उन खदानों से आ रहा है जो वेनेजुएला के कुख्यात हिंसक गिरोह ट्रेन डी गुआयाना के रहमीकरण पर चलती हैं। इसके पूरे खेल में स्थानीय गैंग्स की मौज हो गई है जिन्हें 20% तक कट मनी (रंगदारी) मिल रही है।हक की बात करने वाले मजदूरों को धमकीवेनेजुएला का मुख्य खनन हब अल कारल्लाओं में होता हो जा दुनिया के सबसे हिंसक और भ्रष्ट इलाकों में गिना जाता है। खनन कंपनियों के दफ्तरों में आज भी दर्जनों सैन्य अधिकारी तैनात हैं। जब मजदूर अपने हक की मांग करते हैं, तो उन्हें आतंकवाद के झूठे मामलों में फंसाने और नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती हैं।

अल सिस्समा के बिना अमेरिका नहीं पहुंचती खेप: खदानों में काम करने वाली स्थानीय मजदूरों की सहकारी कमेडियों के मुखियाओं ने खुलासा किया कि हर महीने

निकाले जाने वाले कुल सोने का 20% हिस्सा सीधे स्थानीय अंडरवर्ल्ड गैंग ट्रेन डी गुआयाना को जाता है। इलाके में इस रंगदारी का बाकायदा अल सिस्तेमा कहा जाता है। अवैध ब्रिगेड से जुटाया गया सोना सरकारी कंपनी मिनरवेन के पास पहुंचता है, जिसे ट्रेफिगुरा को बेचे जाने वाले सोने के साथ ही एक ही भट्ठी में पिघला दिया जाता है। यानी अमेरिकी विमानों से वाशिंगटन पहुंच रहे सोने में सीधे तौर पर हिंसक गैंगस्टर की संलिप्तता होती है।

अमेरिकी कंपनियां खदानें हथियाने में जुटीं: ट्रेफिगुरा ने सरकारी कंपनी मिनरवेन के साथ साल भर का एग्रीमेंट किया, जिसके तहत हर महीने करीब 400 किलोग्राम सोना अमेरिका ले जाया जाने लगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों और कानूनी दायित्वों के डर से यह पूरी डील अधर में लटक गई है।

अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाएगा भारत का एस्सार ग्रुप, ट्रंप ने एलान कर क्या कहा



वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की एस्सार ग्रुप की एक बड़ी परियोजना का अनावरण किया। आयोवा में 15 अरब रुपये के निवेश से एक विशाल स्टील प्लांट बनाने की है पहल की गई है। व्हाइट हाउस ने बताया कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र होगा। इस घोषणा से अमेरिकी उद्योग को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ अमेरिका में रोजगार के नए अवसर पैदा की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने इसे ट्रंप की प्रतिबद्धता बताया है।

एस्सार ग्रुप और ट्रंप ने क्या कहा: ट्रंप ने ओबेल ऑफिस में एस्सार ग्रुप के सह-

संस्थापक रवि रुइया और उनके बेटे रेवंत रुइया की मौजूदगी में सोमवार को निवेश संबंधी घोषणा की।

ट्रंप ने कहा, आज, हम यह घोषणा करते हुए उत्साहित हैं कि मेसाबी मेटालिक्स आयोवा राज्य में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बनाएगा। एस्सार ग्रुप के मेसाबी मेटालिक्स के अध्यक्ष रेवंत रुइया ने अमेरिका में चीजों के निर्माण के महत्व को वापस लाने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि मेसाबी मेटालिक्स का लक्ष्य 2030 तक इस प्लांट में उत्पादन शुरू करना है। यहां सालाना

10 दस लाख टन स्टील का उत्पादन होने का अनुमान है।

देश में सबसे बड़ा: सालाना 10 दस लाख टन स्टील का उत्पादन: प्लांट शुरू होने के बाद आयोवा राज्य में 1,750 स्थायी रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता डेलर रोजर्स ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी उद्योग के पुनर्निर्माण, विनिर्माण को वापस लाने और नए रोजगार सृजित करने के अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज की यह घोषणा अमेरिकी स्टील उद्योग को पुनर्जीवित करने के राष्ट्रपति के ऐतिहासिक

प्रयासों को रेखांकित करती है। इस घोषणा की खबर सबसे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी थी। पूर्वी आयोवा में यह नया मिल मेसाबी मेटालिक्स द्वारा बनाया जा रहा है। यह मिनेसोटा-आधारित कंपनी भारत के एस्सार ग्रुप के स्वामित्व में है। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्लांट पूरी तरह से बनने पर सालाना 10 दस लाख टन स्टील का उत्पादन करेगा। यह अमेरिका में किसी भी अन्य प्लांट से अधिक होगा।

खदान और रोजगार का क्या है महत्व इस प्लांट के लिए आवश्यक लौह अयस्क मिनेसोटा में एक नई खदान से आएगा।

जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर ने सुनी 222 आवेदकों की समस्याएं



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर स्वर्णा दीवान ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 222 आवेदकों की समस्याएं सुनीं उन्होंने आवेदकों से उनकी शिकायतों और समस्याओं की जानकारी लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए डिप्टी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक

प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी ली और पात्रता एवं नियमों के अनुसार निराकरण सुनिश्चित करने को कहा उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए जिन प्रकरणों का तत्काल निराकरण संभव नहीं है उनमें स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर निर्धारित अवधि में कार्रवाई पूरी की जाए साथ ही संबंधित आवेदकों को की गई कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए जनसुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे और अपने-अपने विभागों से संबंधित आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए जानकारी प्रस्तुत की।

पुरानी पेंशन से लेकर वेतन विसंगतियों तक 23 मांगें, कर्मचारी संघ ने संभागायुक्त के माध्यम से CM-चीफ सेक्रेटरी को भेजा ज्ञापन



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की रीवा संभागीय इकाई ने प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लंबित और न्यायोचित मांगों के निराकरण को लेकर मंगलवार को 23 सूचीय मांगों का ज्ञापन संभागायुक्त रीवा संभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम सौंपा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय आयुक्त के प्रतिनिधि संभागीय उपायुक्त पिपूष भट्ट को ज्ञापन दिया संघ ने



ज्ञापन से मांगों पर समय-सीमा निर्धारित कर शीघ्र सकरात्मक निर्णय लेने की मांग की है ज्ञापन सौंपने के दौरान राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, प्रदेश संयुक्त महामंत्री डॉ. कृष्णराज सिंह, संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश

तिवारी, संभागीय सचिव डॉ. गोविन्द नारायण श्रीवास्तव, संभागीय संयुक्त सचिव एवं आईटी सेल सह प्रभारी प्रीती उपाध्याय सहित रीवा, सीधी और मऊजंज समेत संभाग के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। संघ के संभागीय सचिव डॉ. गोविन्द

नारायण श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारी हित से जुड़ी मांगों और पूर्व में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए शासन को लगातार ज्ञापन दिए जाते रहे हैं उन्होंने विशेष रूप से अधिकारी-कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, कर्मचारी

आयोग के गठन और दो संतान की बाध्यता समाप्त करने संबंधी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।
पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग: 23 सूचीय ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वरिष्ठता के साथ पुनः लागू करने और ग्रेज्युटी की अधिकतम सीमा केंद्र के समान 25 लाख रुपए करने की मांग प्रमुख है इसके अलावा कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान लिथि से महंगाई भत्ता देने की मांग रखी गई है संघ ने लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान, स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का पूर्ण लाभ तथा विभिन्न विभागों में लंबित वेतन विसंगतियों के निराकरण की मांग की है इसके लिए स्वतंत्र राज्य वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है।

नियमितकरण और पदोन्नति पर जोर: ज्ञापन में दैनिक वेतनभागी, सविदा और स्थाई कर्मियों को रिक्त पदों के विरुद्ध

नियमित करने तथा उसके बाद ही शेष पदों पर सीधी भर्ती करने की मांग की गई आउटसोर्स तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासकीय सेवक मान्यता देने की मांग भी शामिल है पंचायत सचिवों के पंचायत विभाग में सविलियन, शिक्षकों की योग्यता एवं विषयवार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, स्वास्थ्य विभाग की वेतन विसंगतियां दूर करने और महिला एवं बाल विकास विभाग की सविदा पर्यवेक्षकों के नियमितकरण की मांग की गई है।

पटवारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मुद्दे भी शामिल: संघ ने पटवारियों के पदोन्नति नियमों में बदलाव कर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की मांग की है ज्ञापन में प्रथम समयमान की सविदा को 2800 ग्रेड पे के अनुरूप करने तथा रजिस्ट्री से संबंधित कार्य कराए जाने पर आवश्यक उपकरण, ज्ञापन और अतिरिक्त मानदेय उपलब्ध कराने की मांग रखी गई।

स्वनिधि योजना से छोटे कारोबार को मिली रफ्तार, सांसद ने लाभार्थियों से जाना अनुभव

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान के तहत सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने मंगलवार को सीधी नगर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स से संवाद किया सांसद ने विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों और टेला-व्यवसाय संचालित करने वाले लाभार्थियों के बीच पहुंचकर योजना से मिली आर्थिक सहायता, कारोबार की स्थिति और व्यवसाय के अनुभवों की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों की समस्याएं और सुझाव भी सुने। संवाद के दौरान छोटे व्यापारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से मिली आर्थिक सहायता उनके लिए कारोबार को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित हुई है पूंजी की



उपलब्धता से उन्हें अपने छोटे व्यवसाय में आवश्यक सामग्री जुटाने, कारोबार को व्यवस्थित करने और उसे आगे बढ़ाने में मदद मिली लाभार्थियों ने योजना से पहले और बाद में व्यवसाय की स्थिति में आए बदलावों की जानकारी भी सांसद के साथ साझा की सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट

वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे व्यवसायियों को कारोबार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिससे वे अपने व्यवसाय को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी

स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सड़क किनारे दुकान लगाने वाले वेंडर्स से लेकर छोटे दुकानदारों तक बड़ी संख्या में लोग अपने व्यवसाय के माध्यम से परिवार का भरण-पोषण करते हैं ऐसे में उन्हें संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध होना कारोबार को स्थिरता देने में मददगार है। सांसद ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के साथ ही लाभार्थियों से सीधे संवाद कर योजनाओं के वास्तविक प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना है उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वे शासन की अन्य पात्रता आधारित योजनाओं की जानकारी लेकर उनका भी लाभ उठाएं और अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं।

मऊ ब्लॉक में लगा सेवा संकल्प कैंप, 15 विभागों के स्टॉल पर मिल रही योजनाओं की जानकारी



मीडिया ऑडीटर, चित्रकूट (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान के तहत चित्रकूट जिले के मऊ ब्लॉक परिसर में विशेष कैंप का आयोजन किया गया है कैंप में ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं और विभागीय सेवाओं की जानकारी देने के लिए करीब 10 से 15 सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं अभियान के दौरान लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याओं के समाधान और

स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ब्लॉक परिसर में लगाए गए कैंप में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और समूह से संबंधित विभागों सहित अन्य सरकारी विभागों की भागीदारी है अलग-अलग स्टॉल पर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहकर ग्रामीणों को संबंधित योजनाओं, पात्रता और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं इससे ग्रामीणों की विभिन्न विभागों

के कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही स्थान पर कई योजनाओं की जानकारी मिल रही है।

योजनाओं की जानकारी के साथ समस्याओं का समाधान: कैंप में पहुंचने वाले लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन दिया जा रहा है कृषि से जुड़ी योजनाओं, खेती-किसानी से संबंधित जानकारी तथा पशुपालन विभाग की योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को बताया जा रहा है वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर भी लोगों को उपलब्ध सुविधाओं एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों की स्वास्थ्य

समस्याओं की जानकारी लेकर आवश्यक परामर्श और उपचार की सुविधा दी जा रही है आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है।

4 अक्टूबर तक चलेगा अभियान: सेवा संकल्प अभियान के तहत लगाया गया यह कैंप 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोगों को सेवाएं और योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगे प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से कैंप का लाभ लेने की अपील की गई है मऊ के खंड विकास अधिकारी संजय पांडे, पशु चिकित्सा अधिकारी रवि शंकर गौतम सहित कृषि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कैंप में मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं।

‘जाने इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, फिर भी लता की आवाज युगों तक गूंजेगी



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के जन्मदिवस के अवसर पर नगर की अग्रणी संगीत संस्था रिदम म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रिदम थियेटर में विशेष संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में ग्रुप से जुड़े कलाकारों ने

लता मंगेशकर के सदाबहार गीत प्रस्तुत कर उन्हें भावपूर्ण ढंग से याद किया कलाकारों ने उनके हजारों गीतों में से चुनिंदा गीतों की प्रस्तुतियां दीं जिन्हें सुनकर संगीत प्रेमी भावविभोर हो उठे। कार्यक्रम में रिदम म्यूजिकल ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. विनोद तिवारी ने लता मंगेशकर से जुड़ी अपनी स्मृतियां साझा करते हुए कहा कि, जाने इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, फिर भी लता की आवाज युगों तक विश्व में गूंजती रहेगी उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर की आवाज भारतीय संगीत को ऐसी अमूल्य विसम है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद करती रहेगी कार्यक्रम में हिन्दू धर्म परिषद के संस्थापक नारायण

डिगवानी और संरक्षक अवधेश श्रीवास्तव की गरिमामय उपस्थिति रही मंच का संचालन संस्था के उपाध्यक्ष अनीला शर्मा ने किया, जबकि महासचिव पीयूष मिश्रा ने अतिथियों एवं कलाकारों का स्वागत किया कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने लता मंगेशकर के लोकप्रिय गीतों को अपनी आवाज में प्रस्तुत कर संगीत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की रिदम म्यूजिकल ग्रुप से जुड़े कलाकारों की प्रस्तुतियों को उपस्थित लोगों ने सराहा बताया गया कि रिदम म्यूजिकल ग्रुप द्वारा समय-समय पर संगीत क्षेत्र से जुड़ी महान हस्तियों के जन्मदिवस एवं विशेष अवसरों पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जाता है।

मनकामेश्वर मंदिर गरबा महोत्सव में 11 गुणों के 300 कलाकार मंच पर बिखेरेंगे रंग

रीवा। शहर के मनकामेश्वर मंदिर परिसर में आगामी 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले गरबा महोत्सव-2026 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं हिन्दू धर्म परिषद द्वारा आयोजित इस महोत्सव को भव्य स्वरूप देने के लिए आयोजन स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है आयोजकों के अनुसार इस बार नवदुर्गा के अवसर पर मनकामेश्वर मंदिर परिसर में नगर के प्रमुख डांस एवं गरबा गुणों के करीब 300 कलाकार मंच पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे आयोजन प्रभारी संजय तिवारी मुन्नु ने बताया कि गरबा महोत्सव के लिए अब तक 11 डांस गुणों ने पंजीयन कराया है इनमें हिमालय, डायनामाइट, कुशल एंड कुशल, लर्निंग, करन, बाल एंड बादल, स्टायलिश सहित शहर के अन्य चर्चित



गरबा एवं डांस गुण शामिल हैं इन गुणों से जुड़े करीब 300 कलाकार अलग-अलग प्रस्तुतियों के माध्यम से महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बनेंगे।
भव्य पंडाल और आकर्षक मंच की तैयारी: हिन्दू धर्म परिषद की ओर से मनकामेश्वर मंदिर परिसर में इस

बार बड़े पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है आयोजन को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए मंच, प्रकाश व्यवस्था तथा दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है आयोजकों का कहना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और दर्शकों के पहुंचने की संभावना को

देखते हुए पंडाल में पर्याप्त बैठक व्यवस्था रखी जाएगी महोत्सव की खास बात यह होगी कि दर्शकों से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा श्रद्धालु और शहरवासी पांच दिनों तक होने वाले गरबा महोत्सव में निःशुल्क शामिल होकर कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद ले सकेंगे महोत्सव के मुताबिक गरबा आयोजन के दौरान धार्मिक वातावरण के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी प्रमुखता दी जाएगी।

प्रतिदिन होगी भजन संध्या: आयोजन के वरिष्ठ मार्गदर्शक डी.पी. सिंह परिहार के मार्गदर्शन में महोत्सव के दौरान प्रतिदिन भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा इससे गरबा महोत्सव के साथ धार्मिक संस्था में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समन्वय देखने को मिलेगा शाम के

समय होने वाली भजन प्रस्तुतियों में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है आयोजन प्रभारी संजय तिवारी ने बताया कि महोत्सव को लेकर कलाकारों और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को सहयोग देने वाले गुणों की प्रस्तुतियों की तैयारी और मंच संचालन की रूपरेखा पर भी काम चल रहा है आयोजन स्थल पर सुरक्षा, बैठक, मंच और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं हिन्दू धर्म परिषद का प्रयास है नवदुर्गा के अवसर पर होने वाला यह आयोजन शहरवासियों के लिए धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक मनोरंजन का भी अवसर बने पांच दिवसीय गरबा महोत्सव में अलग-अलग डांस गुणों की प्रस्तुतियां और प्रतिदिन होने वाली भजन संध्या मुख्य आकर्षण रहेगी।

छुहिया घाटी में फिल्मी वारदात! ओडिशा पुलिस की कस्टडी से तस्क़र आदित्य को छुड़ा ले गए बदमाश



छुहिया घाटी में 3 गाड़ियों से घेरकर फायरिंग, बेसबॉल बैट से पुलिस वाहन में तोड़फोड़, मिर्च स्प्रे का भी इस्तेमाल



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मंगलवार को ओडिशा पुलिस की टीम पर आदित्य मिश्रा को पुलिस हिरासत से रीवा-सीधी सीमा पर स्थित छुहिया घाटी में हमला कर NDPS मामले के आरोपी छुड़कर ले जाने का मामला सामने आया है।

घटना के बाद सीधी और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार हमलावर कई वाहनों में पहुंचे थे और पुलिस वाहन को आगे-पीछे से घेर लिया था विभिन्न रिपोर्टों में वाहनों की संख्या तीन और चार बताई गई है बताया गया कि ओडिशा पुलिस की टीम आदित्य मिश्रा को रीवा जिला न्यायालय में पेश करने के लिए लेकर आ रही थी यमपुर नैकिन थाना क्षेत्र की छुहिया घाटी से गुजरे समय पहले से मौजूद हमलावरों ने पुलिस वाहन को रोक लिया इसके बाद पुलिस टीम पर हमला किया गया और आरोपी को अपने कब्जे से छुड़कर हमलावर फरार हो गए।

मी सुचना: हमले के दौरान पुलिस वाहन पर फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है उपलब्ध जानकारी के अनुसार तीन बार गोली चलने की सूचना है वाहन के कांच टूटे हैं और एक टायर में गोली लगने की जानकारी भी सामने आई है बेसबॉल बैट से वाहन में तोड़फोड़ किए जाने की बात भी रिपोर्टों में कही गई है पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे किए जाने की सूचना भी सामने आई है हालांकि घटना में किसी पुलिसकर्मियों का घायल होने की जानकारी फिलहाल नहीं है ओडिशा पुलिस की टीम में आठ पुलिसकर्मियों होने की जानकारी सामने आई है घटना के बाद टीम ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी इसके बाद सीधी पुलिस ने आसपास के थानों को सतर्क करते हुए आरोपी और हमलावरों की तलाश शुरू की।

बताया गया है कि हमलावरों के वाहनों के मेहर की ओर जाने की सूचना मिली है।
पुलिस सुरक्षा पर उठे सवाल: घटना ने पुलिस हिरासत में ले जाए जा रहे आरोपी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं तीन-चार वाहनों में पहुंचे लोगों द्वारा पुलिस वाहन को घेरना, हमला करना और आरोपी को छुड़कर ले जाना अब जांच का प्रमुख बिंदु है पुलिस को यह पता लगाना होगा कि आरोपी के आने के रस्ते और पुलिस टीम की गतिविधि की जानकारी हमलावरों तक कैसे पहुंची। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि क्या आरोपी को छुड़ने की योजना पहले से बनाई गई थी या घटना अचानक हुई पुलिस हमलावरों की पहचान, वाहनों की जानकारी और घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर एक अक्टूबर को विशेष स्वास्थ्य शिविर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 1 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय सीधी में वृद्धजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय के नवीन ओपीडी हॉल स्थित एनसीडी कक्ष में किया जाएगा सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय सीधी डॉ. दीपा रानी इसरानी ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम दीर्घायु का युग लम्बे जीवन के लिए व्यवस्थाओं का पुनर्विचार रखी गई है थीम के अनुरूप शिविर में वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जांच एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्कूलों से ही मजबूत हो

शिक्षा मंत्रालय नीट, जेईई और ऐसी ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग पर निर्भरता घटाने के लिए जो पहल करने जा रहा है, उसमें सफलता तब मिलेगी, जब स्कूली स्तर पर और विशेष रूप से 11वीं एवं 12वीं की कक्षाओं में पठन-पाठन का स्तर उन्नत होगा। यह निजी के साथ सरकारी स्कूलों में भी उन्नत होना चाहिए। और भी अच्छा होगा कि आठवीं के बाद ही जब छात्र विज्ञान एवं गणित विषयों का चयन करते हैं, तभी से उनके पाठ्यक्रम और

प्रश्नपत्रों का स्तर ऐसा किया जाए, जिससे वे आगे चलकर नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में कोचिंग का सहारा लेने के लिए विवश न हों। एक समय था, जब इंटरमीडिएट के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां बदलीं और फिर कोचिंग के चयन ने एक बड़े उद्योग का रूप ले लिया। इसका कारण हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के पठन-पाठन के स्तर में कमी के

साथ यह भी रहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर कठिन होता गया।

समझना कठिन है कि जिस स्तर के प्रश्न उक्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी स्तर के प्रश्न 11वीं और 12वीं परीक्षाओं में क्यों नहीं शामिल किए जा सकते? आखिर जब पाठ्यक्रम एक है तो स्कूली और प्रतियोगी परीक्षाओं

में प्रश्नों का स्तर अलग-अलग क्यों? निःसंदेह यह अंतर इसलिए आया, क्योंकि शिक्षा बोर्डों का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में सफल बनाना होता है और वह भी अच्छे नंबरों से। यह किसी से छिपा नहीं कि आजकल कुछ शिक्षा बोर्डों की परीक्षाओं में 90 प्रतिशत अंक लाना बहुत आम हो गया है। शिक्षा

बोर्डों और साथ ही विद्यालयों का उद्देश्य छात्रों को केवल स्कूली परीक्षाओं में पास होने लायक ही नहीं, बल्कि मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना भी होना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि शिक्षा मंत्रालय ने यह समझा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को तैयार करने में एनसीईआरटी के साथ दूसरे शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम को भी आधार बनाने की आवश्यकता है,

लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति तब होगी, जब केंद्रीय और राज्यों के शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में साम्य होगा। शिक्षा मंत्रालय को यह भी समझना होगा कि केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को ही कोचिंग संस्कृति से बचाने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यकता अन्य परीक्षाएं देने वाले छात्रों के संसर्ग में भी है। इसी के साथ उसे ट्यूशन संस्कृति पर भी विराम लगाने पर विचार करना चाहिए।

टेलीकॉम कंपनियों पर लगी लगाम- उपभोक्ता हित में जरूरी नियमन

सौरभ वार्षणेय

देश की अर्थव्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र की भूमिका अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मोबाइल फोन और इंटरनेट संचार के साधन भर नहीं रह गए हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, व्यापार, रोजगार और सरकारी सेवाओं तक पहुंच का बूनियादी जरूरत बन चुके हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सेवा की गुणवत्ता, शुल्क की पारदर्शिता, स्पैम कॉल, डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता शिकायतों जैसे मुद्दों पर बढ़ती नियामकीय सख्ती इसी बदलती जरूरत का संकेत है।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के रूप से उपभोक्ताओं को सस्ते डेटा और अनेक सेवाओं का लाभ मिला है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी उठे हैं। अनचाहे कॉल और संदेश, अस्पष्ट शुल्क, खराब नेटवर्क, शिकायतों के समाधान में देरी और निजी डेटा की सुरक्षा जैसे मुद्दे लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। जब कोई सेवा करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए, तब केवल व्यावसायिक लाभ पर्याप्त नहीं माना जा सकता। बाजार की ताकत के साथ उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही भी जरूरी है। इसी संदर्भ में रिचार्ज की वैधता का सवाल खास महत्व रखता है। मोबाइल सेवा अब ऐसी जरूरत है, जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज करना संभव नहीं। 28 दिन वाले मासिक रिचार्ज को लेकर मार्च 2026 में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में सवाल उठाया थाकि 12 महीनों के वर्ष में 28 दिन की वैधता वाले चक्र से उपभोक्ता को प्रभावी रूप से साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ सकता है। उन्होंने उन उपभोक्ताओं के लिए भी क़िफायती विकल्पों की जरूरत बताई, जिन्हें मोबाइल डेटा की आवश्यकता नहीं है।यह बहस अब नियामकीय बदलाव तक पहुंच चुकी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को टेलीकॉम कॉन्ज्युमर्स प्रोटेक्शन अमेंडेंट रगुलैसेंस, 2026 अधिसूचित किए हैं। नए प्रावधानों के तहत कंपनियों को उन वैधता अवधियों के अनुरूप वॉइस और एसएमएस ऑनली स्पेशल टैरिफ वॉउचर्स उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें 30 दिन या उससे कम अवधि वाले डेटा-बंडल प्लान शामिल हैं। इसके अलावा समान तरीख पर हर महीने नवीनीकरया वाला विकल्प और लंबी वैधता वाला कम-से-कम एक वॉइस एसएमएस ऑनली विकल्प भी उपलब्ध कराना होगा। इन वाउचर में उचित टैरिफ कटौती का भी प्रावधान है।

इस बदलाव का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि हर उपभोक्ता को समान प्रकार की सेवा की जरूरत नहीं होती। बुजुर्ग, फीचर फोन उपयोगकर्ता, सीमित डेटा इस्तेमाल करने वाले या कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए केवल कॉल और एसएमएस की सुविधा पर्याप्त हो सकती है। यदि उन्हें अनावश्यक डेटा के साथ बंडल प्लान लेने के लिए मजबूर होना पड़े, तो चॉइस' का अर्थ ही कमजोर हो जाता है। नियमन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार भुगतान कर सके। हालांकि, 30 दिन का विकल्प उपलब्ध होना अपने आप में अंतिम समाधान नहीं है। असली सवाल यह होगा कि कंपनियां इन प्लान को कितनी आसानी से उपलब्ध कराती हैं और उनकी कीमत क्या रखती हैं। यदि वॉइस एसएमएस ऑनली प्लान केवल नियमों की खानापूर्ति के लिए बनाए जाएं, उनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध न हो या उनकी कीमत डेटा वाले प्लान के मुकाबले पर्याप्त रूप से कम न हो, तो उपभोक्ता को वास्तविक लाभ सीमित रह जाएगा। इसलिए पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी इस व्यवस्था की सफलता की अनिवार्य शर्त हैं। टेलीकॉम नियमन का दायरा केवल रिचार्ज तक सीमित नहीं है। स्पैम कॉल और अनचाहे व्यावसायिक संदेश भी उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा बड़ा प्रश्न है। बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट और अन्य सेवाओं के नाम पर आने वाले लगातार प्रचार संदेश कई बार धोखाधड़ी का माध्यम भी बन जाते हैं। ऐसे में वैध व्यावसायिक संचार और संदिग्ध गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर करना तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना जरूरी है। हड्डेटा सुरक्षा भी इसी जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन खरीदारी और सरकारी सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के बीच टेलीकॉम कंपनियों के पास उपभोक्ताओं से संबंधित बड़ी मात्रा में जानकारी रहती है। इस जानकारी की सुरक्षा केवल कानूनी अनुपालन का विषय नहीं, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिकों के विश्वास का आधार है।

कुमार कृष्णन

नदी में गाद दिखते ही हमारी नजर नदी पर नहीं, गाद पर टिक जाती है। हमें लगता है कि नदी का तल भर गया है, इसलिए पानी रुक रहा है; गाद निकाल देगे तो नदी गहरी हो जाएगी और बाढ़ का संकट कम हो जाएगा। लेकिन नदी इतनी सरल गणित नहीं है। जिस गाद को हम नदी की समस्या कह रहे हैं, वही गाद नदी के स्वभाव और उसकी यात्रा का हिस्सा भी है। तो फिर सवाल यह है कि समस्या गाद है या गाद का असंतुलित जमाव? यदि गाद निकालना ही समाधान है तो हर बरसात के बाद नदी फिर क्यों भर जाती है? और यदि गाद नदी के साथ चलने वाली प्राकृतिक तलछट है तो उसे हटाने से पहले यह कौन तय करेगा कि कहां से कितनी गाद निकालनी है और कहाँ उसे नदी के साथ बहने देना है?

बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों को लेकर यह सवाल अब केवल बाढ़ के मौसम का नहीं रह गया है। यह नदी-विज्ञान, जल-प्रबंधन, पर्यावरण और विकास की दिशा का सवाल है। वर्षों से गाद निकालने की मांग उठती रही है। सरकारों ने समितियां बनाईं, विशेषज्ञों ने अध्ययन किए और न्यायिक संस्थाओं के स्तर पर पर्यावरणीय सवाल उठाे। फिर भी बहस बार-बार उसी जगह लौट आती है—गाद निकालें या नहीं?

असल सवाल इससे आगे का है—गाद क्यों जमा हो रही है और नदी का संतुलन कैसे कायम रखा जाए?

15 सितंबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने 'बिहार जलस्रोत पुनर्संस्थान एवं गाद

प्रबंधन नीति, 2026' को मंजूरी दी। नीति में नदियों, बराजों और जलाशयों से गाद निकालकर उनकी जलधाराओं और जलबहन क्षमता बहाल करने तथा निकाली गई गाद का सड़क, रेल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा और निर्माण कार्यों में उपयोग करने की बात कही गई है।

नीति की जरूरत समझी जा सकती है, लेकिन इसकी सफलता मशीनों से निकलने वाली गाद की मात्रा से नहीं मापी जानी चाहिए। कसौटी यह होनी चाहिए कि गाद निकालने के बाद नदी का व्यवहार क्या बदला? क्या बाढ़ का पानी बेहतर ढंग से निकला? क्या कहीं दूसरे हिस्से में कटाव बढ़ा? क्या तलछट फिर उसी स्थान पर जमा हुई? क्या जलीय जीवन प्रभावित हुआ?

इन सवालों का महत्व इसलिए भी है कि गाद पर बनी पुरानी समितियां हमें पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं।

2001 में पूर्व केंद्रीय जल आयोग अध्यक्ष डॉ. बी. के. मित्तल की अध्यक्षता में बनी समिति ने गाद जमाव और बाढ़ के संबंधों की पड़ताल की थी। सरकारी अभिलेखों में दर्ज निष्कर्षों के अनुसार बड़ी नदियों में व्यापक स्तर पर गाद निकासी को सामान्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान नहीं माना गया। हालांकि विशेष परिस्थितियों वाले कुछ हिस्सों में तकनीकी और आर्थिक अध्ययन के बाद लक्षित गाद निकासी की संभावना स्वीकार की गई।

2016 में केंद्र ने माधव चितले समिति का गठन गंगा में भीमगोड़ा से फरक्का तक गाद प्रबंधन और ड्रेजिंग के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से किया। समिति ने नदी के प्रत्येक हिस्से की अलग प्रकृति को समझने पर

लोकतंत्र बचाने जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा?

सनत जैन

देश इस समय एक ऐसे संवैधानिक संकट के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां सवाल केवल मतदाता सूची में नाम रहने या कटने का नहीं है। बल्कि सवाल नागरिक होने के अधिकार का है। चुनाव आयोग को लेकर देशभर में उठ रहे सवाल, एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप और अब न्याय पालिका की भूमिका पर उठती उंगलियां लोकतंत्र नागरिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए बेहद गंभीर संकेत हैं।

सत्य हिंदी के एक कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं चुनाव मामलों के जानकार अरुण अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश और महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा ने जिस तरह इन सवालों पर चर्चा की, उसने पूरे विवाद को एक नए राजनीतिक- संवैधानिक आयाम में पहुंचा दिया है। विशेष रूप से अरुण अग्रवाल द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के संबंधों तथा

न्यायिक नियुक्तियों को लेकर लगाए गए आरोपों ने कई असहज प्रश्न खड़े किए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और न्यायिक जांच अलग विषय है। लेकिन लोकतंत्र में इतने गंभीर आरोपों का सामने आना भी अपने आप में चिंता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस चुनाव आयोग के फैसले से करोड़ों नागरिकों के मतदान के अधिकार समाप्त कर दिए गए। उसके खिलाफ न्यायपालिका कितनी तेजी और कितनी निष्पक्षता से हस्तक्षेप कर रही है? यह चुनाव आयोग की मदद कर रही है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों ने यह प्रश्न पैदा किया है। कहीं प्रक्रिया इतनी जटिल तो नहीं बना दी गई कि सामान्य नागरिक अपने ही नागरिक अधिकार को साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रह जाए? मतदान केवल एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं है। मतदान नागरिकता की मौलिक अधिकारों की एक राजनीतिक अभिव्यक्ति है। मतदाता सूची से नाम हटाना केवल चुनाव से बाहर होना नहीं, बल्कि

लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आवाज को खो देना है। अंग्रेजों के शासनकाल में केवल पढ़े लिखे कुछ लोगों को ही मतदान का अधिकार था। स्वतंत्रता के पश्चात बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान मतदान के अधिकार दिए गए।सत्ता में सभी की भागीदारी एक समान रखी गई। इसलिए जब लाखों-करोड़ों नामों के हटने के आंकड़े सामने आते हैं, तो चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका तक हर संवैधानिक संस्था की जवाबदेही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर और भी बढ़ जाती है। यह वह बिंदु है जहां न्याय पालिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान ने न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा का अधिकार और सर्वोच्चता न्यायपालिका को संविधान ने प्रदान की है। संविधान और जनता अदालत से यह अपेक्षा नहीं करती, वह किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति के पक्ष में खड़ी हो। जनता केवल यह चाहती है कि संविधान और न्याय के पक्ष में न्यायलय निर्णय करें। यदि

न्यायपालिका को लेकर यह धारणा बनने लगे, वह सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं के बीच उठ रहे विवादों में निष्पक्ष निर्णायक की भूमिका नहीं निभा रही है। तो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ ही कमजोर हो जाएगा और लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र स्थापित होने में देर नहीं लेगी।। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लेकर कार्यक्रम में लगाए गए आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण तथ्य, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया ही कर सकती है। लेकिन आरोपों को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका सर्वोच्च है, इसलिए उसके खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। यदि आरोप गलत हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच हो और उसका तथ्यात्मक खंडन होना चाहिए। यदि उनमें कुछ सत्य है, तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है। जब गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल पछुने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। आज जनता के सामने मूल प्रश्न यही है।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान एमपी में रच रहा है नया इतिहास

हर्षवर्धन पान्डे

संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी इस अभियान के चार मूल स्तंभ हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का का स्पष्ट संदेश है कि उनकी सरकार अब सिर्फ राजधानी या कार्यालयों से नहीं चलेगी। वह गांव-गांव, वार्ड-वार्ड पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनेगी, योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाएगी और प्रशासनिक व्यवस्था को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएगी। अभियान के दौरान जमीनी भ्रमण के दौरान सादगी और मितव्ययिता पर सरकार विशेष ध्यान रख रही है।इस वर्ष जुलाई में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फैसला लिया कि हर शुक्रवार को मंत्रालय, जिला और संभाग स्तर पर नियमित बड़ी बैठकें नहीं होंगी। पूरा प्रशासन फील्ड में रहेगा। 7 अगस्त से शुरू हुआ यह मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान जनवरी 2027 तक चलेगा।

छिंदवाड़ा से इस अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने खुद जनसुनवाई की। शिकायतों के आधार पर उन्होंने तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), एक तहसीलदार और एक पटवारी को निर्वाचित करने के निर्देश दिए। यह प्रदेश में बड़े एक्शन की सिर्फ शुरुआत थी।फिर अगले हफ्ते बाद बड़वानी में 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' के दौरान उन्होंने डिप्टी कलेक्टर समेत सात अधिकारियों-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। इनमें दो पटवारी, दो मुख्य



नगरपालिका अधिकारी, एक सहायक अभियंता और एक जनपद पंचायत सीईओ शामिल थे।

बीते आगस्त माह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीकमगाढ़ का दौरा किया और यहाँ आम जनता की समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत टीकमगाढ़ में सीएम हेल्पलाइन में नागरिकों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका निराकरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला पंजीयक सहकारिता को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी सतत रूप से ग्राउंड पर उतरकर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लें। स्थानीय स्तर पर जनता की शिकायतों का समय सीमा में प्रभावी निराकरण किया जाये।इस तरह की कार्रवाई लोगों के मन में यह विश्वास पैदा कर रही है कि शिकायत दर्ज करने के बाद अब मध्यप्रदेश में सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि लापरवाह अधिकारियों पर अब तुरंत गाज गिरेगा। एमपी का जन-विश्वास अभियान' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन की कार्यशैली में पारदर्शिता और नए बदलाव का प्रतीक है।



किसी शुक्रवार को कोई शासकीय अवकाश हो, तो मोहन सरकार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित होने वाला जनविश्वास शिविर उस दिन के बजाय शनिवार को आयोजित किया जाता है ताकि जनता की समस्याओं का समाधान और संवाद बाधित न हो। मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर और विभाग के अधिकारी फील्ड में मौजूद रहकर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, लोक सेवा गारंटी के लॉबित मामलों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याएँ मौके पर ही सुलझ जाएँ।अब हर शुक्रवार को प्रदेश भर में जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर तक जनता दबावर लगाते देखे जा रहे हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद भी विभिन्न जिलों में पहुंचकर सुनवाई कर रहे हैं। वे न सिर्फ शिकायतों की गहन समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि प्रागतिशील किसानों, निवेशकों, क्षेत्र की महत्वपूर्ण हस्तियों,

व्यापारियों, किसानों, युवाओं से भी संवाद भी कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि अभियान सिर्फ शिकायत निवारण तक सीमित नहीं, बल्कि विकास कार्यों को गति देने और जनसहभागिता बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। 'नो-मीटिंग डे' सरीखे आयोजनों के माध्यम से अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, जनता का विश्वास जीतने वाले नेता की छवि जोड़ प्रदेश में बनाते जा रहे हैं। जन समस्याओं के आनलाइन समाधान के लिए जन विश्वास अभियान पोर्टल का आगाज सीएम डॉ. मोहन यादव कर चुके हैं। जन-विश्वास अभियान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह शासन को आम आदमी के द्वार तक ले जा रहा है।

गांव की महिलाएं, किसान, युवा और छोटे व्यापारी अब सीधे अधिकारी से आमने सामने बात कर पा रहे हैं। इस बड़ी पहल के माध्यम से जहां कई जगहों पर कस्बों से पड़ी शिकायतें हल हो रही हैं वहीं सरकार को तमाम योजनाओं का आम जनता को लाभ मिल रहा है और प्रशासनिक उदासीनता, अफसरों की मनमानी, लाल फीताशाही पर पूरी तरह से अंकुश लग रहा है।आज मध्यप्रदेश में 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है। अभियान के पहले माह ही 11 प्रशासन में 5,64,000 से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निपटारा किया है। साथ ही लोक सेवा गारंटी के तहत दर्ज 8,06,000 से अधिक आवेदनों का समाधान भी अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है जो इस अभियान की सफलता

को बता रहा है। 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान','नो-मीटिंग डे' सरीखे आयोजनों ने मध्यप्रदेश में 'सरकार जनता के द्वार' की अवधारणा को सही मायनों में व्यवहारिक रूप प्रदान करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के एक्शन में होने के चलते प्रशासन को भी अब पहली बार को मैदान में उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब प्रशासन और अधिकारी खुद लोगों के बीच जाकर उनकी पीड़ा सुन रहे हैं तो उनको भी जमीनी हकीकत पता चलती है और इस पर अगर तुरंत कार्रवाई करते हैं, तो सरकार के प्रति जन-विश्वास निरंतर मजबूत होता है। बीते माह केद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के शाहगंज में आयोजित मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे जन-विश्वास अभियान की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर चुके हैं और इसे जनता की सेवा और शासन के प्रति विश्वास को मजबूत करने वाला एक बेहतरीन अभियान बताया है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह अभियान एक तरफ सरकार को जनता के करीब लाकर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है, वहीं यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जेनो-मुखी छवि का बड़ा प्रतीक भी बनता जा रहा है। जनता दिल जीतने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका समस्याओं को सुनना, समाधान करना और जवाबदेही तय करना है। 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' अब इसी राह पर मध्यप्रदेश में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है।

जिले के 9 ग्रामों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना को मिलेगा बढ़ावा, तकनीकी सहयोगी संस्थाओं से 5 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान (DA-JG) के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ग्गपुर के पत्र के आधार पर जिले के 9 ग्राम सभाओं के लिए सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना के प्रस्तुतीकरण एवं क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है इसके तहत चयनित ग्रामों में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए तकनीकी सहयोगी संस्था, सिविल सोसायटी संगठन अथवा स्थानीय संस्था के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है जिला प्रशासन के अनुसार चयनित संस्था द्वारा ग्राम सभाओं को वन अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के माध्यम से आजीविका संवर्धन, वन प्रबंधन में अभिसरण, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया के अंतर्गत दावा निर्धारण, पारंपरिक सीमाओं का सीमांकन एवं मानचित्रण तथा सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित

गतिविधियों में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा 9 ग्रामों में शामिल किए गए वन क्षेत्र सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना के लिए जिले के 9 ग्रामों का चयन किया गया है इनमें खड़वां विकासखंड के ग्राम पंचायत सिंवत के ग्राम सिंवत में खसर क्रमांक 568-पी का 140.000 हेक्टेयर तथा ग्राम पंचायत रतनपुर के ग्राम रतनपुर में खसर क्रमांक 634-पी का 147.932 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है इसी प्रकार भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत नेरुवा के ग्राम नेरुवा में खसर क्रमांक पी-12 का 207.038 हेक्टेयर ग्राम पंचायत कमजी के ग्राम कमजी में खसर क्रमांक पी-172 का 195.990 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत मुकील के ग्राम मुकील में खसर क्रमांक पी-174 का 203.254 हेक्टेयर,ग्राम पंचायत कोटडोल के ग्राम कोटडोल में खसर क्रमांक पी-15 का 120.000 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत रूसनी के ग्राम रूसनी में खसर क्रमांक पी-37 का 270.000 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत बंछे के ग्राम बंछे में खसर क्रमांक पी-123 का 286.933 हेक्टेयर तथा ग्राम पंचायत जनीरा के ग्राम जनीरा में खसर क्रमांक पी-151 का 250.250 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में गूजी पोषण और जनजागरूकता की बात न्योता भोज, अन्नदान, स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता और पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता से दिया सुपोषण का संदेश

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम चैनपुर के ग्राम पंचायत भवन में पोषण माह 2026 के तहत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्योता भोज सहित विभिन्न जन जागरूकता एवं पोषण आधारित गतिविधियां आयोजित कर महिलाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य उजित नारायण सिंह रहे विशिष्ट अतिथियों के रूप में चैनपुर सरपंच मीना कुमारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास मनेन्द्रगढ़ शशि जायसवाल, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक आरती टोप्पो, उपसरपंच मदन सिंह तथा पंच अकरम,



कोमल प्रसाद, राजकुमारी, हीराकली एवं बबली उपस्थित रहे महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया कार्यक्रम का संचालन परियोजना मनेंद्रगढ़ ग्रामीण की पर्यवेक्षक शिल्पा अग्रवाल ने किया उन्होंने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा दीदियों के योगदान को सम्मानित किया जा रहा है साथ ही पोषण माह के दौरान हितग्राहियों से संवाद कर

बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीयां साझा की जा रही है परियोजना अधिकारी शशि जायसवाल ने महिलाओं से संवाद करते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी अन्य शुभ अवसरों पर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में न्योता भोज का आयोजन कर बच्चों के साथ खुशियां साझा की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि कुपोषित बच्चों के उपचार एवं पोषण सुधार के लिए चिरमिरी में विशेष कैप आयोजित किया जा

रहा है जिसमें पात्र कुपोषित बच्चों का शासन द्वारा निःशुल्क उपचार किया जाएगा न्योता भोज और अन्नदान से दिया सुपोषण का संदेश ग्राम पंचायत भवन परिसर में आयोजित न्योता भोज के अंतर्गत 25 बच्चों को भोजन कराया गया जबकि अन्न दान महादान पहल के तहत 20 गर्भवती महिलाओं को भोजन कराया गया इस दौरान स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता के अंतर्गत चयनित बच्चों के पालकों को 5 सुपोषण टोकरी प्रदान की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों से संवाद कर 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया खिलौना दान और हर घर मुन्गा अभियान को मिला बढ़ावा चैनपुर सरपंच द्वारा खिलौना दान योजना के अंतर्गत 25 बच्चों को स्लेट वितरित की गई वहीं हर घर मुन्गा घर-घर मुन्गा अभियान के तहत ग्राम परिसर में मुन्गा के पीधे लगाए गए।

जनसुनवाई में शराब दुकान हटाने, स्कूल मैदान कब्जामुक्त कराने की मांग



मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को हुई जनसुनवाई में ग्रामीणों ने शराब दुकान हटाने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और पंचायतों में निर्माण कार्यों की जांच कराने की मांग की। इस दौरान ग्रामवासी आदिवासी बस्ती के पास संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग की महिलाओं ने बताया कि 11 सितंबर को विरोध के बाद अधिकारियों ने 15 दिन में दुकान हटाने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने शांतिधाम की सर्वे नंबर 1559, 1560 और 1562 की जमीन को

संदिर और आदिवासी बस्ती के पास संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग की महिलाओं ने बताया कि 11 सितंबर को विरोध के बाद अधिकारियों ने 15 दिन में दुकान हटाने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने शांतिधाम की सर्वे नंबर 1559, 1560 और 1562 की जमीन को

भी अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की वहीं अमरपुर के ग्रामीणों ने सरकारी एकीकृत माध्यमिक विद्यालय के मैदान पर कब्जे की शिकायत की उनका आरोप है कि सर्वे नंबर 170 की जमीन पर 20 सितंबर को तारफेसिंग कर दी गई जिससे बच्चों के खेलने की जगह कम हो गई है खनियाधाना के पिपरोदा आलम और लोहादेवी के ग्रामीणों ने पंचायतों में निर्माण कार्यों में कथित अनियमितता की शिकायत की ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन, सीसी रोड, प्रशिक्षण शाला, चौपाल और पुलिया के लिए राशि निकालने के बावजूद कई काम नहीं हुए या उन्हें कागजों में पूरा दर्शाया गया उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की।

मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। मेडिकल कॉलेज के सामने शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की राजस्व और पुलिस अमले की मौजूदगी में जेसीबी से टीन शेड से बनी 34 दुकानों को तोड़ा गया इसके साथ ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बाहरी हिस्से में दुकानों के सामने बनाए गए अवैध चबूतरों को भी हटाय़ा गया प्रशासन के मुताबिक कार्रवाई के बाद करीब 12 बीघा शासकीय जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई एक साल में कई बार दिए गए नोटिस तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित लोगों को पिछले एक



साल में कई बार नोटिस जारी किए गए थे इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटया गया इसके बाद प्रशासन ने बेदखली का आदेश जारी किया और मंगलवार को मौके पर कार्रवाई की गई प्रशासन के अनुसार मेडिकल कॉलेज के सामने पाल समाज के कुछ लोगों ने पिछले कई वर्षों से शासकीय जमीन पर टीन शेड बनाकर दुकानें संचालित कर रखी

थीं इनमें से कुछ दुकानें किएए पर भी दी गई थीं प्रशासन को इन दुकानों से हर महीने करीब दो लाख रुपए किराया वसूले जाने की जानकारी मिली थी इसके अलावा मौके पर रात के समय कथित रूप से अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की जानकारी भी प्रशासन के संज्ञान में आई थी विरोध करने पर छह लोगों पर कार्रवाई अतिक्रमण



हटाने के दौरान कुछ लोगों ने विरोध और हंगामा किया पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए दो महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखा, जिससे किसी अग्रिय स्थिति से बचा जा सके कार्रवाई पूरी होने के बाद सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कर दिया गया।

छत पर सौर पैनल, बिजली बिल में बड़ी राहत-सेवा संकल्प अभियान में सामने आई राजेश कुमार राय की आत्मनिर्भरता की कहानी

राजेश कुमार राय को मिली 1.08 लाख की सब्सिडी, केंद्र के 78 हजार और राज्य के 30 हजार रुपए से आसान हुआ सोलर पैनल लगाना



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। कभी हर महीने आने वाला बिजली का बिल परिवार के घरेलू बजट का एक हिस्सा तय

करता था बिजली की जरूरतें बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ता था ऐसे में यदि घर की छत ही बिजली उत्पादन का माध्यम बन जाए और

हर महीने आने वाला बिजली बिल लगभग शून्य हो जाए तो यह किसी रहस्य से कम नहीं है। मनेन्द्रगढ़ निवासी राजेश कुमार राय के लिए यह बदलाव प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से संभव हुआ है। उनके घर की छत पर लगा सोलर पैनल न केवल बिजली की जरूरत पूरी करने में मदद कर रहा है बल्कि परिवार को बिजली खर्च में भी बड़ी राहत दे रहा है राजेश कुमार राय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कराया। उन्होंने बताया कि

सोलर पैनल स्थापित करने में लगभग 1 लाख 99 हजार रुपये की लागत आई योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये, इस प्रकार कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई सब्सिडी मिलने से सोलर पैनल स्थापित करने का आर्थिक भार काफी कम हुआ और उनके लिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना आसान हो गया सोलर पैनल लगा तो बिजली बिल में आई बड़ी राहत राजेश कुमार राय बताते हैं कि सोलर पैनल लगने के बाद उनके बिजली

खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले उन्हें निर्भरित रूप से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब उनका बिजली बिल लगभग शून्य आ रहा है। इससे परिवार के मासिक खर्च में बचत हो रही है और बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा अपनाने का लाभ केवल आर्थिक बचत तक सीमित नहीं है स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का अवसर भी मिला है योजना के तहत मिलने वाली

सब्सिडी ने उनके जैसे परिवारों के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना अधिक सुलभ बनाया है राजेश कुमार राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा

कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से उनके परिवार को बिजली खर्च में राहत मिली है उन्होंने कहा कि योजना का लाभ मिलने से सौर ऊर्जा के प्रति उनकी सोच बदली है।



बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे बैगा समाज के लोग, जनसुनवाई में आए 58 आवेदन



मीडिया ऑडिटर, अनूपपुर (निप्र)। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में बैगा समाज के प्रतिनिधियों ने बिजली, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं खाती और अमलई क्षेत्र के ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंप जनसुनवाई में कुल 58 आवेदन प्राप्त हुए खाती के सरपंच भदर सिंह नेटी ने अपर कलेक्टर को 10 सुत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसमें वाई क्रमांक 1 और 2 की बैगा बस्ती में बिजली व्यवस्था शुरू कराने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पांच मुख् सड़कों के निर्माण की मांग की गई सरपंच ने खाती में एसटी बालक छात्रावास, खेल मैदान और सरकारी बैंक शाखा खोलने की मांग भी रखी उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन वर्ष 2023 से तैयार है लेकिन अभी तक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं हुई हैं इससे ग्रामीणों को इलाज के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ रहा है इधर अमलई में पिछले करीब 30 दिनों से नल-जल योजना बंद होने से ग्रामीण पेयजल संकट से परेशान हैं ग्रामीणों ने सचिव गजू सोनी को ज्ञापन सौंपकर जल्द पेयजल व्यवस्था बहाल कराने की मांग की।

किसानों की आय बढ़ाने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर जोर विभागों को लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश

मीडिया ऑडिटर, अनूपपुर (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाघार में मंगलवार को केंद्रीय नोडल अधिकारी शशांक मिश्रा ने कुपक कल्याण से जुड़े कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया गया पशुपालन विभाग को टीकाकरण और कुत्रिम गर्भाधान के निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। किसानों को मत्स्य पालन तथा कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने की बात भी कही गई नोडल अधिकारी ने एफपीओ के माध्यम से किसानों की उपज की व्र्वि व्यवस्था मजबूत करने और प्रभावी मार्केटिंग चैनल विकसित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके बैठक के बाद शशांक मिश्रा ने जमुडी स्थित बायो रिसोर्स सेंटर और राइस मिल का निरीक्षण किया उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि पद्धतियों तथा कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को लेकर चर्चा की इस दौरान कलेक्टर रत्नाकर झा, जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी सहित कृषि पशुपालन, उद्यानिकी मत्स्य पालन सहकारिता नाबाई लीड बैंक और आजीविका मिशन के अधिकारी मौजूद रहे।

निर्माणाधीन मकान की पानी की टंकी में डूबी 2 साल की मासूम, मौत

मीडिया ऑडिटर, नर्मदापुरम (निप्र)। बाबई रोड पर सोमवार दोपहर निर्माणाधीन मकान की पानी की टंकी में डूबने से 2 साल की मासूम नित्या धुवे की मौत हो गई घटना के समय उसके माता-पिता मजदूरी करने गए थे और बच्ची अपनी दो बहनों के साथ घर के पास खेल रही थी नित्या के पिता बंटी धुवे बैलून के रहने वाले हैं और परिवार मजदूरी के लिए नर्मदापुरम आया था कैंपियन स्कूल के पास निर्माणाधीन मकान के नजदीक परिवार ने झोपड़ी बना रखी है।

संक्षिप्त समाचार

रायसेन में बस ने ऑटो को मारी टक्कर

एक गंभीर घायल, भोपाल जा रहा था, वाहन जल



मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन से भोपाल जा रही तेज रफ्तार बस ने सोमवार को नोमखड़ा पुल के पास सड़क किनारे खड़े ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में तीन लोग सवार थे, जिनमें एक को गंभीर चोट आई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो पलट गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस का आगे का कांच भी टूट गया। बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जिनमें कुछ को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद बस चालक बस लेकर भोपाल की ओर निकल गया। सूचना मिलने पर खरबई पुलिस ने बस को रोककर सैंडोरा चौकी में खड़ा कराया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सैंडोरा चौकी प्रभारी शैलेंद्र दायमा ने बताया कि बस रायसेन से भोपाल जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को सैंडोरा चौकी लाया गया।

सीहोर में देर रात बेकाबू कार मोबाइल शोरूम में घुसी

कांच का दरवाजा चकनाचूर, डिस्प्ले काउंटर को भी नुकसान



मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर के आनंद डेरी चौराहे पर सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मोबाइल शोरूम में घुस गई। यह हादसा इतना तेज था कि दुकान का मुख्य कांच का दरवाजा टूटकर बिखर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सफेद रंग की यह कार चौराहे के पास अचानक बेकाबू हो गई और सीधे दुकान के अंदर जा घुसी। घटना के बाद दुकान के सामने और अंदर कांच के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। मौके पर भीड़ जमा हो गई हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। हालाँकि, दुकान के सामने वाले कांच और डिस्प्ले काउंटर को काफी नुकसान हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दुकान के बाहर फैले कांच के टुकड़े हटाए गए।

खरगोन में गांजे की खेती पर कार्रवाई, पौधे जल

मीडिया ऑडीटर, खरगोन (निप्र)। खरगोन पुलिस ने चैनपुर क्षेत्र में सोमवार को गांजे की खेती पर कार्रवाई की। महाराष्ट्र सीमा से लगे शेडो एरिया के दो खेतों से 59.74 क्विंटल गांजे के पौधे जल किए गए। पुलिस ने इनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई है। कार्रवाई जामली और गुवाड़ा के ठाटा फलिया गांव में हुई। एसपी रवींद्र वर्मा ने बताया कि 27 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दंगलिया, मधू, सुखलाल और जागीर के खेतों में गांजे की खेती की जा रही है जिसके बाद कार्रवाई की गई। आरोपियों पर NDPS एक्ट में कार्रवाई जामली के खेत से 9,391 पौधे मिले। इनका वजन 3,765 किलो बताया गया है। पुलिस ने इसकी कीमत 1.88 करोड़ रुपए बताई। वहीं, गुवाड़ा के खेत से भी 5,800 पौधे जल किए गए। इनका वजन 2,209 किलो था। इसकी कीमत 1.10 करोड़ रुपए है। पुलिस ने एकट की धारा 8/20 के तहत केस दर्ज किए हैं। चार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

हिंदी पखवाड़े के समापन पर साहित्य और संगीत का हुआ मनोहारी संगम

मीडिया ऑडीटर, बिदिशा (निप्र)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिदिशा में हिंदी पखवाड़े का आयोजन 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच किया गया। पखवाड़े के समापन के दिवस महाविद्यालय के हिंदी विभाग, संगीत विभाग एवं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के संयुक्त प्रयास से समापन समारोह एवं स्वर कोकिला लता मोशकर की जयंती का रंगारंग आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सामूहिक आयोजन में साहित्य और संगीत का संगम हुआ।

खंडवा में युवाओं के लिए रोजगार के 327+ अवसर

1 अक्टूबर को आईटीआई में रोजगार मेला, सिंगाजी प्लांट में 127 से ज्यादा पदों पर आवेदन का मौका

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के दो बड़े अवसर सामने आए हैं। शासकीय आईटीआई खंडवा में 1 अक्टूबर को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश की विभिन्न कंपनियां तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में करीब 200 युवक-युवतियों की भर्ती करेंगी।

वहीं, जिले में स्थित संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत 127 से अधिक रिक्तियां जारी की गई हैं। यानी युवाओं के पास निजी क्षेत्र में नौकरी के साथ-साथ काम सीखने और प्रशिक्षण पाने के भी अवसर उपलब्ध हैं।

1 अक्टूबर को आईटीआई में लगेगा रोजगार मेला: जिला रोजगार अधिकारी लक्ष्मण सिंह सिलौटे ने बताया कि शासकीय आईटीआई खंडवा में 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिस मेले का आयोजन होगा। मेले में प्रदेश की अलग-अलग कंपनियां शामिल होकर अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।

मेले में करीब 200 बेरोजगार युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।



खास बात यह है कि इसमें अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, सभी ट्रेड के डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवा आवेदन/चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच

होना जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को संबंधित कंपनियों के नियमानुसार 8 हजार से 20 हजार रुपए तक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

मेले में जाते समय ये दस्तावेज साथ ले जाना जरूरी: रोजगार मेले में शामिल होने वाले युवाओं को अपने समस्त मूल दस्तावेजों की

नर्मदापुरम में पानी की टंकी में डूबी मासूम बच्ची, मौत

निर्माणाधीन मकान की टंकी में खेलते समय हादसा, बैतूल से मजदूरी करने आया



मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम के बाबई रोड पर सोमवार दोपहर निर्माणाधीन मकान की पानी की टंकी में डूबने से 2 साल की मासूम नित्या धुर्वे की मौत हो गई। घटना के समय उसके माता-पिता मजदूरी करने गए थे। बच्ची अपनी दो बहनों के साथ घर के पास खेल रही थी।

मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। नित्या पिता बंटी धुर्वे बैतूल की रहने वाली थी। परिवार मजदूरी के लिए नर्मदापुरम आया है। बाबई रोड स्थित कैपियन स्कूल के पास मुकेश तिवारी का मकान निर्माणाधीन है। इसी के पास बंटी ने पत्नी और तीन बेटियों के साथ झोपड़ी बना रखी है। आसपास उसके अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं। सोमवार दोपहर बंटी और उसकी पत्नी मजदूरी के लिए इंशान परिसर गए थे। इसी दौरान तीनों बेटियां घर के पास खेल रही थीं। खेलते समय नित्या निर्माणाधीन मकान की पानी की टंकी में गिर गई। बड़ी बहन ने शोर मचाकर नाना को बताया। परिजनों ने बच्ची को बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रात 11:30 बजे मर्ग कायम: देहात थाना प्रभारी ऊषा मरावी ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे मर्ग कायम किया गया है।

गधे की फोटो लगाकर भरा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ?2050 जमा करते ही जारी हुआ सर्टिफिकेट

भोपाल। मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने काउंसिल की ऑनलाइन प्रक्रिया की जांच के लिए एक ऐसा आवेदन किया जिसमें आवेदक के नाम की जगह डंकी, फोटो में गधे की तस्वीर, पिता के नाम में डंकी फादर, माता के नाम में डंकी मदर और जाति के कॉलम में एनिमल दर्ज किया गया। इसके बावजूद आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने का दावा किया गया है। परमार के मुताबिक आवेदन में पता भी मनमाने तरीके से दर्ज किया गया था इसके अलावा 10वीं और 12वीं के अंक तथा रोल नंबर भी वास्तविक दस्तावेजों के बजाय मनगढ़ंत जानकारी के रूप में भरे गए।



ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर भोपाल नर्सिंग कॉलेज और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (BMHRCL) का नाम दर्ज किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि ट्रेनिंग कॉन्प्लीशन सर्टिफिकेट और डिग्री अथवा डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जगह दो खाली कागज अपलोड किए गए

इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत 2050 रुपए फीस जमा की गई। परमार का दावा है कि 25 सितंबर को भुगतान करने के करीब पांच मिनट बाद ही ऑनलाइन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो गया इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और डिजिटल साइन भी दिखाई दे रहे हैं।

सत्यापन प्रक्रिया पर उठाए सवाल: रवि परमार ने इस पूरे मामले को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तकनीकी और प्रशासनिक खामी बताया है उनका कहना है कि यदि बिना वास्तविक शैक्षणिक दस्तावेजों और पहचान संबंधी जानकारी के रजिस्ट्रेशन जारी हो सकता है तो वास्तविक आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है उन्होंने यह भी आशंका जताई कि ऐसी व्यवस्था का गलत इस्तेमाल फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार करने में किया जा सकता है परमार ने MPNRC की ऑनलाइन व्यवस्था संचालित करने वाली एजेंसी MP Online की भूमिका की भी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि आवेदन किस स्तर पर सत्यापन के बिना आगे बढ़ और सर्टिफिकेट किस प्रक्रिया के तहत जनरेट हुआ।

कागपुर पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व में दुर्लभ यूरोपियन

रोलर सहित कई देशी-प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी दर्ज

53.5 हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ विशेष पक्षी सर्वेक्षण, जैव विविधता संरक्षण और ईको-टूरिज्म की संभावनाओं को मिलेगा बढ़ावा

मीडिया ऑडीटर, बिदिशा (निप्र)। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में घोषित कागपुर पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व, बिदिशा में पक्षियों की उपस्थिति एवं क्षेत्रीय जैव विविधता का आकलन करने के उद्देश्य से विशेष पक्षी सर्वेक्षण आयोजित किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्रीमती समीता राजौरा के निदेशानुसार वन विभाग एवं भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी की संयुक्त टीम द्वारा सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया गया। सर्वेक्षण का संचालन वनमंडलाधिकारी (DFO) बिदिशा श्री हेमंत यादव के मार्गदर्शन में भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मो. खालिक, उप वनमण्डलाधिकारी बिदिशा श्री रमेश गहलोत तथा वन विभाग के अमले द्वारा किया गया। टीम ने कागपुर के प्राकृतिक जलस्रोत तथा इसके आसपास के लैंडस्केप में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति का अवलोकन एवं दस्तावेजीकरण किया।

दुर्लभ यूरोपियन रोलर की उपस्थिति प्रमुख आकर्षण: सर्वेक्षण के दौरान कागपुर क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण देशी एवं प्रवासी पक्षियों को देखा गया। सर्वेक्षण का प्रमुख आकर्षण अत्यंत दुर्लभ प्रवासी पक्षी यूरोपियन रोलर (European Roller) की उपस्थिति रही। इस पक्षी की मौजूदगी कागपुर क्षेत्र में उपलब्ध अनुकूल प्राकृतिक आवास एवं समृद्ध प्रास्थितिक तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाती है। यूरोपियन रोलर के अलावा सर्वेक्षण में यूरेशियन कूट, स्पॉट-बिल्ड डक, व्हिस्लिंग विल, ओपन-बिल स्टॉक और वूली-



नेकड स्टॉक जैसे प्रवासी पक्षियों की भी उपस्थिति दर्ज की गई। इन पक्षियों का क्षेत्र में दिखाई देना कागपुर जलस्रोत के महत्व को और अधिक रेखांकित करता है।

स्थानीय पक्षी प्रजातियों की भी समृद्ध उपस्थिति: प्रवासी पक्षियों के साथ-साथ कागपुर क्षेत्र में अनेक स्थानीय पक्षी प्रजातियां भी पाई गईं। इनमें ग्रीन बी-ईटर, स्पॉटेड आउलेट, स्कैली-ब्रेस्टेड मुनिया, पाइड किंगफिशर, ब्लैड-थ्रोटेड किंगफिशर, कॉमन मैना और स्पॉटेड डब प्रमुख रूप से शामिल हैं। स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की इस विविधता से स्पष्ट होता है कि कागपुर क्षेत्र पक्षियों के लिए भोजन, जल एवं प्राकृतिक आवास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित हो रहा है।

53.5 हेक्टेयर में फैला है प्राचीन प्राकृतिक जलस्रोत: बिदिशा तहसील के अंतर्गत 53.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला कागपुर का प्राचीन जलस्रोत बेतवा एवं बाह्य नदियों के

►► कम वर्षा को देखते हुए जल उपलब्धता पर विशेष ध्यान

वर्तमान में कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए वन विभाग द्वारा कागपुर क्षेत्र के जलाशयों में समीपस्थ जल स्रोतों से पानी भरने की व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य जलाशयों में पर्याप्त जल उपलब्धता बनाए रखना है, ताकि अगामी शीतकाल में आने वाले प्रवासी पक्षियों को अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध हो सके। वन विभाग द्वारा जल उपलब्धता के साथ-साथ पक्षियों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

►► वैज्ञानिक प्रबंधन योजना और नियमित पक्षी निगरानी की तैयारी

आने वाले समय में भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) तथा पक्षी विशेषज्ञों के सहयोग से कागपुर पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। इसके साथ ही नियमित पक्षी निगरानी तंत्र विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इस पहल से कागपुर क्षेत्र में पक्षियों की प्रजातियों, उनकी संख्या, मौसमी आवागमन तथा आवास की स्थिति का नियमित वैज्ञानिक आकलन संभव होगा।

►► जैव विविधता संरक्षण के साथ ईको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

कागपुर पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व में दर्ज देशी एवं प्रवासी पक्षियों की विविधता क्षेत्र के जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक प्रबंधन, नियमित निगरानी और जलस्रोतों के संरक्षण के माध्यम से इस क्षेत्र को भविष्य में प्रकृति एवं पक्षी पर्यटन (ईको-टूरिज्म) के संभावित स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। कागपुर में पक्षी सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी क्षेत्र की जैव विविधता के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वन विभाग एवं पक्षी विशेषज्ञों के समन्वित प्रयासों से आने वाले समय में कागपुर पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व में संरक्षण गतिविधियों को और सुदृढ़ किए जाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

मध्य स्थित है। प्राकृतिक जलस्रोत और आसपास का भू-दृश्य यही कारण है कि यह क्षेत्र विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए देशी एवं प्रवासी पक्षियों को अनुकूल आवास उपलब्ध कराता है। प्राकृतिक शरणस्थल के रूप में महत्वपूर्ण बनकर उभर रहा है।

● सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में 127 से ज्यादा अवसर

दूसरा अवसर जिले के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत उपलब्ध है। योजना के अंतर्गत 127 से अधिक रिक्तियां जारी की गई हैं। इसमें चयनित युवाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि संबंधित कार्य को करते हुए व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर भी मिलेगा। प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य के अनुसार, इस योजना के लिए 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा तथा स्नातक स्तर की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग, नॉन-इंजीनियरिंग दोनों क्षेत्र के स्नातक अभ्यर्थी पात्र हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान चयनित युवाओं को 8 हजार से 10 हजार रुपए तक का मानदेय दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।

● नौकरी के साथ प्रशिक्षण का भी मौका

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत युवाओं को संस्थान में काम करते हुए संबंधित क्षेत्र का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे अभ्यर्थियों को अपने तकनीकी या शैक्षणिक ज्ञान को वास्तविक कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करने का अनुभव मिल सकता है।

सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की रिक्तियों के लिए पात्रता, उपलब्ध ट्रेड/रिक्तियां और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी mmsky.mp.gov.in पोर्टल पर देखी जा सकती है।

● युवाओं के लिए दो अलग-अलग अवसर

खंडवा जिले के युवाओं के लिए दोनों अवसरों में योग्यता और समयसीमा अलग है। आईटीआई खंडवा का रोजगार मेला 1 अक्टूबर को एक दिन के लिए आयोजित होगा, जबकि मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत सिंगाजी प्लांट की रिक्तियों के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे युवा अपनी शैक्षणिक योग्यता और रुचि के अनुसार दोनों अवसरों में शामिल हो सकते हैं।

छायाप्रतियां, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार निर्धारित तिथि और समय पर शासकीय कार्ड और रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आईटीआई खंडवा में उपस्थित होकर अभ्यर्थी कार्ड साथ लेकर पहुंचना होगा। कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

सागर में 1 अक्टूबर से अग्निवीर भर्ती रैली

10 जिलों के 11 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल, 24 घंटे मेडिकल टीम रहेगी तेनात

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर में शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 से 14 अक्टूबर तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भर्ती को लेकर जिला प्रशासन और सेना ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी अनुराग सुजानिया ने सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर के कर्नल पंकज कुमार के साथ भर्ती स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

इस भर्ती रैली में सागर, शिवपुरी, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, रघोपुर, भिंड, भुरना और ग्वालियर सहित 10 जिलों के करीब 11 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे।

आईडी स्कैनिंग से लेकर बायोमेट्रिक व्यवस्था देखी: कलेक्टर ने भर्ती स्थल पर अभ्यर्थियों की आईडी कार्ड स्कैनिंग, टी-शर्ट वितरण, रजिस्ट्रेशन सेल और बायोमेट्रिक व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तैयार किए गए दौड़ ट्रैक की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था भी देखी।



कलेक्टर ने सेना के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। परिसर में साफ-सफाई, पेयजल और पर्याप्त संख्या में शौचालय की व्यवस्था समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।

8 लेन एक्सप्रेस-वे से खाई में गिरी दो कार

सास-बहू समेत 4 की मौत, 8 घायल, मुंबई की तरफ जा रहे थे पंजाब-गुजरात के परिवार

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह दो हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। 8 घायल हैं। पहले हादसे का समय सुबह करीब साढ़े 4 और दूसरे एक्सीडेंट का वक्त सुबह करीब साढ़े 6 बजे बताया गया है। दोनों कारों में सवार दो-दो लोगों की जान गई है। वे पंजाब और गुजरात के रहने वाले थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

झड़वर को झपकी लगने से गिरी पहली कार: जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया ने कहा- पहला हादसा सुबह करीब साढ़े 4 बजे हुआ। पंजाब का परिवार कार से मुंबई जा रहा था। इसी बीच झड़वर को झपकी लगने से उनकी कार 8 लेन के बीच बनी रेलिंग तोड़ते हुए करीब 30 फीट नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में नरेंद्र कौर (67) और उनकी बहू मनप्रीत कौर (32) की मौत हुई है। सुबह दूसरी गाड़ियों के झड़वर से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जावरा के अस्पताल पहुंचाया। यहां से उनको रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।



दूटी रेलिंग की वजह से दूसरा हादसा: टीआई गडरिया ने कहा कि सुबह करीब साढ़े 6 बजे पुलिसकर्मी मौका मुआयना कर रहे थे, इसी दौरान दूसरी कार हवा में उछलते हुए रोड के बीच बनी बाउंड्री से टकराकर खाई में आ गिरी।

परवीन हुड़ा मुक्केबाजी के 65 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में पहुंचीं, ली शू को 5-0 से हराया

निशियो ,एजेसी। भारत की बॉक्सर परवीन हुड़ा मंगलवार को यहां निशियो जिम्नेजियम में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर एशियन गेम्स में महिलाओं के 65 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गईं। परवीन ने आखिरी दो राउंड में खासतौर पर अपना दबदबा बनाया। उन्होंने पहला राउंड 3-2 के करीबी अंतर से जीता। इस दौरान परवीन ने सावधानी बरतते हुए काउंटर पंच मारे। परवीन ने दूसरे राउंड में अपने हिट्स से दबदबा बनाया, जबकि चीनी बॉक्सर ने भी कुछ पंच मारे। इसके बावजूद, परवीन ने राउंड 5-0 से जीत लिया। भारतीय बॉक्सर तीसरे राउंड में एक बार फिर बेहतर रहीं। उन्होंने सटीक पंच मारे और तीसरा राउंड 5-0 से जीत लिया। सभी पांच जजों ने उनके पक्ष में वोट दिया, जिसमें से तीन ने उन्हें 29-28 और दो ने 30-27 का फैसला दिया। परवीन अब 65 किग्रा के फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका सामना गोल्ड मेडल के लिए चीनी ताइपे की चेन निपन-चिन से होगा। यह मुकाबला कड़ा और रोमांचक होगा। निपन-चिन मौजूदा ओलंपिक और वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। उन्होंने 2023 एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत के अंकुश पंधाल और नरेंद्र भी मंगलवार को अपने-अपने सेमीफाइनल में उतरेंगे। दोनों मुक्केबाज फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। भारत ने एशियन गेम्स में मुक्केबाजी में छह मेडल पक्के कर लिए हैं। सोमवार को कपिल पोखरिया, प्रिया घनघस और लवलीना बोरगोहेन ने अपने-अपने मुकाबले जीते। प्रिया ने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान की मिजगोना समदोवा पर 5-0 से एकतरफा जीत के बाद महिलाओं की 60 किग्रा कैटेगरी में मेडल पक्का कर लिया। इससे पहले दिन में, लवलीना ने कोरिया की सियोंग सुयोन के खिलाफ महिलाओं के 75 किग्रा क्वार्टर फाइनल में 5-0 से मजबूत जीत के साथ अपना मेडल पक्का कर लिया। रविवार को अंकुश, परवीन और नरेंद्र ने अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर तीन पदक सुनिश्चित किए थे। मौजूदा कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन अंकुश ने पुरुषों के 80 किग्रा क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेक्रूज सालिमोव को 5-0 के एकमत फैसले से हराकर भारत को मौजूदा गेम्स में अपना पहला बॉक्सिंग मेडल पक्का किया। इस बीच, परवीन ने भी महिलाओं की 65 किग्रा कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवबखोर खामिदोवा को 5-0 से हराकर अपना मेडल पक्का किया। नरेंद्र ने पुरुषों के +90 किग्रा क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के अदथापोंग सोंतेप को हराकर अपना पदक पक्का किया।



नौरू ढांड ने देश को दिलाया पांचवां गोल्ड, महिलाओं की ट्रेप इंडिविजुअल इवेंट में रचा इतिहास



नागोया,एजेसी। एशियन गेम्स 2026 में भारत को पांचवां गोल्ड मेडल मिल गया है। अपना पहला एशियन गेम्स खेल रही नीरू ढांड ने इतिहास रचा है और महिलाओं की ट्रेप इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल में 28 के एशियन रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है। इस इवेंट में गोल्ड जीतने वाली वह भारत की पहली महिला ट्रेप शूटर हैं। नीरू ने क्वालीफिकेशन में 118 के स्कोर के साथ टॉप किया था। फाइनल में उन्होंने 28 के स्कोर के साथ एशियन रिकॉर्ड बनाया और एशियन गेम्स के इतिहास में ट्रेप इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। इसके अलावा, नीरू एशियन गेम्स में ट्रेप इंडिविजुअल इवेंट में पहली भारतीय मेडलिस्ट हैं। नीरू फाइनल में टॉप फॉर्म में थीं। उनका पहला मिस उनके नौवें शॉट में हुआ, जिससे वह थोड़ी देर के लिए तीसरे नंबर पर आ गईं। लेकिन उन्होंने तीसरी और चौथी सीरीज में परफेक्ट हिट्स के साथ तेजी से वापसी की और 20 शॉट्स में 19 हिट्स के साथ टॉप पर पहुंच गईं। फिर उन्होंने पांचवीं सीरीज में एक शॉट मिस करने के बावजूद अपनी गोल्ड मेडल पोजीशन बनाए रखी। फिर उन्होंने परफेक्ट फाइनल हिट्स के साथ शानदार गोल्ड मेडल जीता। नीरू ने अपने पहले एशियन गेम्स में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने के रास्ते में 30 में से सिर्फ दो शॉट मिस किए। चीन की युन्योंग सन ने 26 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि कुवैत की निशानेबाज ने 21 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। कॉन्टिनेंटल शोपीस के इस एडिशन में शूटिंग में यह भारत का दूसरा गोल्ड है। कुल मिलाकर, यह आइची-नागोया में भारत का पांचवां गोल्ड है। इससे पहले, नीरू ने आज आशिया अहलावत और मनीषा कीर के साथ ट्रेप टीम शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय टीम ने तीन दिन चले 125-शॉट वाले क्वालीफिकेशन राउंड के बाद कुल 328 का स्कोर बनाया और सिल्वर के लिए कुवैत की चुनौती को पीछे छोड़ दिया।

एशियन गेम्स 2026 में गुलवीर ने लगाई मेडल की हैट्रिक



नागोया ,एजेसी। गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रचते हुए मेडल की हैट्रिक पूरी कर ली है। भारतीय धावक ने मंगलवार को मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। गुलवीर ने इस रेस को 13:32.75 सेकंड में पूरा किया। बहरीन के

बिरहानु बालेव ने 13:30.79 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि जापान के यामागुची टोमोनोरी 13:31.43 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इससे पहले उन्होंने एशियन गेम्स 2026 में 10,000 मीटर और 1500 मीटर इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किए थे। इस जीत के साथ गुलवीर बोते 40

5000 मीटर दौड़ में जीता ब्रॉन्ज

साल में एशियन गेम्स के एक ही एडिशन में तीन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उनसे पहले पीटी उमा ने एशियन गेम्स 1986 में चार मेडल जीते थे।

गुलवीर 5000 मीटर फाइनल की शुरुआत में आगे रहने वाले ग्रुप के साथ बने रहे और शुरुआती 2000 मीटर के बाद तीसरे स्थान पर थे। रेस के निर्णायक दौर में भी उन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखी, लेकिन टॉप-2 स्थानों के लिए चुनौती नहीं दे पाए।

इससे पहले गुलवीर ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में यादगार प्रदर्शन करते हुए 28:29.38 का समय लिया और सिल्वर मेडल जीता। वह इस इवेंट में दो एशियन गेम्स मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने इससे पहले 2023 के हांग्जो एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद गुलवीर पुरुषों की 1500 मीटर रेस में एक और सिल्वर मेडल जीता, जिसमें वह अपने पर्सनल बेस्ट समय 3:36.72 के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

श्री चरणी ने रच दिया इतिहास, आईसीसी विमेंस टी20 बॉलिंग रैंकिंग में बनाया नया रिकॉर्ड

दुबई ,एजेसी। भारत की श्री चरणी ने आईसीसी विमेंस टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद बाएं हाथ की स्पिनर अपने करियर के बेस्ट 817 प्वाइंट्स तक पहुंच गईं। श्री चरणी पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में 'वर्ल्ड नंबर-1' गेंदबाज हैं। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के (806 रेटिंग प्वाइंट्स) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसे मेगन ने नवंबर 2018 में बनाया था। चरणी ने भारत की सफल यात्रा में अहम भूमिका निभाई और एशियन गेम्स में अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए भारत को अपना गोल्ड मेडल बचाने में मदद की। एशिया कप 2026 में श्री चरणी ने 12 विकेट लेकर भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 20 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। श्री चरणी ने एशियन गेम्स 2026 में जापान के खिलाफ



10/4 का अपना करियर-बेस्ट प्रदर्शन करते हुए भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में मदद की थी। खिताबी मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 13 रन

देकर 2 विकेट लिए। भारत ने यह मैच 147 रन से जीतकर गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के विरुद्ध 6

सातवें रमा अत्रे महिला टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ भव्य शुभारंभ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने किया उद्घाटन



चंडीगढ़,एजेसी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुए सातवें रमा अत्रे महिला ट्वेंटी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आधिकारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन सीनियर्स महिला टीम से जुड़ी स्टेट टीमों के बीच ऑल इंडिया और यूटी क्रिकेट एसोसिएशन, चंडीगढ़ की खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा दोनों

टीमों को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने जे.पी. अत्रे मेमोरियल क्रिकेट सोसाइटी (रजिस्टर्ड), हरियाणा के सभी सदस्यों को बीसीसीआई से जुड़ी स्टेट टीमों के बीच ऑल इंडिया विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए बधाई दी।

नागल और दक्षिणेश्वर सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचे



नागोया ,एजेसी। एशियाई खेलों में मंगलवार को सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश ने टेनिस के पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर के मैचों में शानदार जीत हासिल की और प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सुमित ने दूसरे दौर में 2023 एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता दक्षिण कोरिया के सेओगवान होंग को 6-4, 6-0 से हराया, जबकि सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिस्नुवतारा पर कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 (2) से जीत दर्ज की। मौसम की खराबी के कारण सोमवार को सुमित और हांग का मैच रोक दिया गया जबकि पहले सेट में सुमित 3-2 से आगे थे। कोरियाई खिलाड़ी ने वापसी की और मंगलवार को फिर से शुरू होने पर पहले आउट अंक जीते क्योंकि सुमित पहले मैच में 3-4 से पीछे था। हालांकि, सुमित ने सेट और बाद में मैच अपने नाम करने के लिए लगातार नौ गेम जीते। सुमित एटीपी मास्टर्स 1000 इंडियन वेल्स क्वालीफाईंग राउंड में हांग से 6-2, 2-6, 6-7 (4) से हार गए थे। नागल ह्वोन चुंग से 6-2, 4-6, 5-7 से हार गए जबकि वह एकल स्पर्धा में सूनवू क्वोन से 1-6, 2-6 से हार गए। एशियाई खेलों में अगले दौर में नागल का मुकाबला उज्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा।

मुक्केबाज अंकुश फाइनल में, नरेंद्र ने जीता ब्रॉन्ज मेडल



निशियो । एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंकुश पंधाल ने पुरुषों के 80 किग्रा सेमीफाइनल में फजलिदीन एर्किनबोव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। अंकुश ने सेमीफाइनल में एर्किनबोव पर 4-1 से शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। अंकुश पहले राउंड के आखिर में 1-4 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे पंचों के साथ करीबी मुकाबले में दूसरा राउंड 3-2 से जीत लिया। तीसरे राउंड में भी भारतीय मुक्केबाज दोनों बॉक्सरों में बेहतर रहे। उन्होंने तीसरा राउंड 5-0 से जीता। पांच में से चार जजों ने अंकुश के पक्ष में वोट दिया और उन्होंने 4-1 से जीत हासिल की। चारों ने 29-28 का फैसला दिया, जबकि एक जज ने उनके खिलाफ 28-29 का फैसला दिया।नरेंद्र अपना सेमीफाइनल मुकाबला ओरलबे से 0-5 के एकमत फैसले से हार गए। ओरलबे ने अपने जोरदार मुक्कों से बाउट पर दबदबा बनाया, जबकि नरेंद्र ने अच्छा खेला, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन को नीचे नहीं गिरा सके।

रन देकर 3 विकेट चटकाए। इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने 754 प्वाइंट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 723 प्वाइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एशियन गेम्स के फाइनल में 79 रन की पारी खेली थी, जिसके साथ उन्होंने टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजी की रैंकिंग में टॉप-5 में वापसी कर ली है। दूसरी ओर, हरारे में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच जारी सीरीज ने वनडे फॉर्मेट में काफी बदलाव किया है। यह सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। वेस्टइंडीज की ऑल-राउंडर हेली मैथ्यूज ने सीरीज के पहले मैच में 182 रनों की दमदार पारी खेली थी, जिसके बाद वह 711 प्वाइंट्स के साथ बैटिंग रैंकिंग में तीन पायदान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गईं। उनकी साथी रियलीना ग्रिमंड 34 पायदान ऊपर चढ़कर 270 प्वाइंट्स के साथ संयुक्त रूप से 102वें स्थान पर पहुंच गईं।

शपथ पुरुषों के ट्रेप इंडिविजुअल फाइनल में पहुंचे, टीम मेडल से चूकी

नागोया ,एजेसी। ट्रेप शूटर शपथ भारद्वाज ने 117 पॉइंट्स के साथ क्वालीफिकेशन में आठवें स्थान पर रहने के बाद पुरुषों के ट्रेप शूटिंग इंडिविजुअल में फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। हांगझोक 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कायनन चेनाई 115 पॉइंट्स के साथ 16वें और अहवर रिजवी 107 पॉइंट्स के साथ 32वें स्थान पर रहे। दोनों फाइनल से चूक गए। शपथ इंडिविजुअल क्वालीफिकेशन में 117 पॉइंट्स के साथ संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर रहे और कतार के मोहम्मद अल-रमाही और कजाकिस्तान के अलीशेर ऐसालबायेव के साथ तीन-तरफा शूट-ऑफ में शामिल हुए, जिसमें फाइनल में दो जगह दांव पर थीं। फिर उन्होंने आखिरी दो जगहों के लिए एक नर्वस तीन-तरफा शूट-ऑफ में जीत हासिल की और अल-रमाही को हराकर मेडल राउंड में अपनी जगह पक्की की।

इस बीच, शपथ, कायनन और अहवर की ट्रेप मेन्स टीम 339 के टोटल स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहने के बाद मेडल से चूक गईं।

इससे पहले, नीरू ढांड, आशिया अहलावत और मनीषा कीर की विमेंस ट्रेप टीम ने मंगलवार को विमेंस ट्रेप टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, जिससे शूटिंग में देश के मेडलों की संख्या 13 हो गई।

तीनों ने 125-शॉट के क्वालीफिकेशन राउंड के तीन दिनों के बाद कुल 328 का स्कोर बनाया और सिल्वर के लिए कुवैत की चुनौती पर जीत हासिल की। चीन ने 346 के टोटल स्कोर के साथ गोल्ड जीता, जबकि कुवैत ने 325 के साथ ब्रॉन्ज



जीता। नीरू ने क्वालीफिकेशन में 118 के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर रहने के बाद इंडिविजुअल फाइनल के लिए भी क्वालीफाई किया। आशिया और मनीषा ने क्रमशः 106 और 104 का स्कोर किया और 16वें और 23वें स्थान पर रहने के बाद फाइनल से चूक गईं।

शूटिंग में 13 मेडल में से भारत के पास सिर्फ एक गोल्ड है, जो मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट से आया है। कमलजीत और सुरुचि सिंह ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। भारत के पदकों की कुल संख्या फिलहाल 46 है, जिसमें 4 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं।

भारत का सर्फिंग अभियान बिना पदक के समाप्त

ताहारा । भारत ने मंगलवार को एशियन गेम्स 2026 में अपना पहला सर्फिंग अभियान बिना किसी पदक के समाप्त किया। किशोर कुमार अनवरसु आखिरी भारतीय थे, जो पुरुषों के शॉर्टबोर्ड क्वार्टर-फाइनल में बाहर हो गए। सर्फिंग ने एशियन गेम्स में आइची-नागोया 2026 में अपना डेब्यू किया और भारत ने ताहारा के पैसिफिक लॉन्ग बीच पर पुरुषों और महिलाओं के शॉर्टबोर्ड कॉम्पिटिशन में चार सदस्यीय समूह उतारा। 18 साल के भारतीय सर्फर किशोर का रन आखिरी के साथ टॉप किया था। फिलीपींस के टोबी एम्पेजोन से 8.53-5.37 की हार के साथ खत्म हुआ। टोबी ने अपनी

दो वेक्स में 5.50 और 3.03 का स्कोर किया, जबकि किशोर सिर्फ 3.00 और 2.37 ही बना सके। सर्फिंग में, किसी कॉम्पिटिटर का स्कोर उसकी सबसे ज्यादा स्कोर वाली दो वेक्स का टोटल होता है, जिसमें हर वेव को 10.00 में से आंका जाता है, जिससे अधिकतम स्कोर 20.00 होता है। किशोर ने तीसरे राउंड में चीन के मा वेनसोंग को 9.76-8.80 से हराकर क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने अपने ओपनिंग-राउंड हीट में भी 9.33 पॉइंट्स के साथ टॉप किया था। भारत के दूसरे मेन्स शॉर्टबोर्ड एटेंट, शिवराज बाबू, दूसरे राउंड में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ

ईरान के दावूद खादिर को 8.96-3.60 से हराकर आगे बढ़े।

शिवराज का कैपेन तीसरे राउंड में खत्म हो गया, जहां वह फिलीपींस के जयुआर्ड एल्सोसे से 11.50-7.83 से हार गए। विमेंस शॉर्टबोर्ड में, कमाली प्रकाश और सुगर शांति गायेन भी तीसरे राउंड में बाहर हो गईं। कमाली इंडोनेशिया की जैस्मीन मिशेल स्टुडर से 1.64-5.93 से हार गई, जबकि सुगर तीसरे राउंड में जापान की मिनामी नोनाका से 14.60-5.17 से हार गई। भारत ने मालदीव में एशियन सर्फिंग

चैंपियनशिप 2024 के जरिए पुरुष और महिला, दोनों कैटेगरी में एशियन गेम्स के कोटे हासिल किए, जहाँ उन्होंने कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में अपना पहला टीम सिल्वर मेडल भी जीता।

सर्फिंग ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में डेब्यू किया और पेरिस 2024 में वापस आया। यह खेल एलए 2028 ओलंपिक में भी शामिल होगा, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के शॉर्टबोर्ड इवेंट होंगे। भारत का ओलंपिक में सर्फिंग में प्रतिनिधित्व करना बाकी है।



अमरनाथ सोनी बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। भारतीय जनता पार्टी (निप्र)। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के अधिवक्ता अमरनाथ सोनी को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन की ओर से नई जिम्मेदारी मिलने पर सोनी ने भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश यादव, क्षेत्रीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी सहित संगठन के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष अमरनाथ सोनी ने कहा कि पार्टी और संगठन ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसका पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और पार्टी की प्रगति

के लिए सक्रियता से कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी सोनी की नियुक्ति पर भाजपा एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल रहा नियुक्ति के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं बधाई देने वालों में विद्यासागर शुक्ला, मंडल प्रभारी प्राणेश ओझा, मंडल अध्यक्ष घनश्याम यादव, महामंत्री ऋषि तिवारी, धनंजय सोनी, बबलू मिश्रा, डॉ. अतिल तिवारी, प्रशांत पाठक, डॉ. सोनल शर्मा, सुधीर सोनी, अविनाश सिंह पहिरार, सुशील चंद्र शुक्ला, मार्तंड सिंह, रजनीश पांडे, ऋषि श्रीवास्तव, तुलाराम पाठक, मंगलेश्वर सिंह, पवन यादव, राजेश यादव, राहुल शुक्ला, पुष्पेंद्र त्रिपाठी, अमित गुप्ता, लालजी चौरसिया, विजय वर्मा, शिव प्रसाद विश्वकर्मा, शिवा शुक्ला, बलराम सोनी, विकास सोनी, छोटे गुप्ता, कैलाश गुप्ता, शंकर केसरवानी, सुनील गुप्ता, मोहम्मद नसीर अंसारी, राजू सिंह, लखन माझी, विजय करुण्य, समीर मिश्रा, संदीप सोनी, छोट्टू श्रीवास्तव सहित कई लोगों ने बधाई दी।

वन स्टॉप सेंटर रीवा के प्रयासों से सुलोचना को मिला अपना परिवार

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। सिरमौर पुलिस द्वारा एक महिला को संरक्षण प्रदान करते हुए वन स्टॉप सेंटर रीवा लाया गया महिला की पहचान सुलोचना वर्मा, पति गौर लाल केवट, पिता जगदीश प्रसाद वर्मा एवं माता जानकी वर्मा लालगांव थाना सिरमौर के रूप में हुई परजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुलोचना के दो बच्चे हैं दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उनकी मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति प्रभावित हुई, जिसके कारण वे काफी परेशान रहने लगीं तथा ठीक से सुनने और ठीक से बोलने और अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असमर्थ थीं इसी दौरान वे अपने परिवार से दूर हो गईं और लगभग 15 दिनों तक भटकती रहीं वन स्टॉप सेंटर रीवा में आने के बाद टीम द्वारा सुलोचना को सुरक्षित एवं आत्मीय वातावरण प्रदान किया गया उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए टीम ने

धैर्यपूर्वक उनकी देखभाल एवं लगातार काउंसलिंग की। महिला द्वारा अपनी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाने के बावजूद टीम ने निरंतर प्रयास करते हुए उनके परिवार एवं निवास स्थान की जानकारी जुटाने का प्रयास किया वन स्टॉप सेंटर की टीम के अथक प्रयासों से अंततः सुलोचना के परिवार का पता लगाया गया और उनके परजनों से संपर्क स्थापित किया गया सुचना मिलने पर परजिन वन स्टॉप सेंटर पहुंचे तथा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 27 सितंबर 2026 को सुलोचना को सुरक्षित रूप से उनके परिवार के सुपुर्द किया गया लंबे समय बाद अपने परजनों से मिलकर सुलोचना के चेहरे पर खुशी और संतोष स्पष्ट दिखाई दिया परजनों ने वन स्टॉप सेंटर रीवा एवं सिरमौर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए टीम के संवेदनशील प्रयासों की सराहना की यह प्रकरण दर्शाता है।

राजीनामा के बहाने बुलाकर युवक से मारपीट, एसपी से शिकायत

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। गढ़ थाना क्षेत्र में पुराने मामले में राजीनामा कराने के बहाने युवक को बुलाकर उसके साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है ग्राम मिमारी, थाना नईझूढ़ी जिला मऊजंग निवासी आशीष पाण्डेय ने पुलिस अधीक्षक रीवा को शिकायती आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है पीछित के अनुसार 20 सितंबर 2026 को शाम करीब 4:30 बजे नीरज गुप्ता ने फोन कर उसे चिरहुला मंदिर के पीछे बुलाया उसे पूर्व में दर्ज एक मामले में राजीनामा करने की बात कही गई थी आरोप है कि मंदिर पहुंचने पर वहां पहले से मौजूद नीरज गुप्ता, रिकू गुप्ता, नीलम

गुप्ता, कंचन गुप्ता और आदर्श गुप्ता ने एकराय होकर उसके साथ लाठी-डंडों और हाथ-पैर से मारपीट की आवेदन में पीछित ने गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया है उसका दावा है कि मारपीट में गाल पर गंभीर चोट आई और तीन टंके लगे जबकि एक दांत भी टूट गया शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आने की बात कही गई है पीछित ने आरोप लगाया कि उसे गंभीर परिणाम भुगतने तथा पत्नी के माध्यम से झूठी शिकायत दर्ज करायी जा रही भिजवाने की धमकी दी गई उसका कहना है कि आरोपी पहले भी रास्ता रोककर विवाद और मारपीट करते रहे हैं जिससे वह भयभीत है पीछित ने एसपी से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है।

अंतरराज्यीय चंदन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 57 किलो लकड़ी और औजार बरामद 4 गिरफ्तार

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अमहिया थाना पुलिस ने चंदन चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 57 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की है जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख 70 हजार रुपए बताई गई है इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल आरी, चाकू और कुल्हाड़ी भी जब की गई हैं आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है बंगले के सामने से काटा था चंदन का पेड़ पुलिस के अनुसार सिविल लाइन कॉलोनी निवासी परियादी ने 17 सितंबर को अमहिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी परियादी ने बताया था कि उनके बंगले के सामने परिसर में लगा चंदन का पेड़ अज्ञात आरोपियों ने काट दिया और उसकी

लकड़ी चोरी कर ले गए शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की मुखबिर की सूचना से आरोपियों तक पहुंची पुलिस जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सदिश्यों के संबंध में सूचना मिली इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस टीम ने सदिश्यों की बेगबंदी कर चार आरोपियों को पकड़। पूछताछ में आरोपियों ने चंदन चोरी की वारदात में शामिल होना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी की गई चंदन की लकड़ी और वारदात में इस्तेमाल औजार बरामद किए गए गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जसरथ पारदी (35), तलकर आदिवासी (35), स्वागात आदिवासी (20), निवासी देवली, जिला मंडला और मारू पावर (22), निवासी सगौनी, जिला दमोह के रूप में हुई है।

मीडियाऑडीटर

रीवा

मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का सभी विभाग शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करें : कमिश्नर

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अटेंड न करने वाले अधिकारियों पर की जाएगी,कार्रवाई कमिश्नर ने निर्देश दिए सभी अधिकारी समय सीमा के पत्रों का जवाब प्रस्तुत करेंगे

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा सभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने मंगलवार को संभागीय समय सीमा की बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-समय पर जिले के भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाओं का सभी विभाग शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करें इस दौरान कमिश्नर ने मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की भी जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन हर हाल में किया जाए कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त सभी शिकायतों को अधिकारी गण प्राथमिकता से अटेंड करें और शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि जो अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को



अटेंड नहीं करते हैं और बिना जवाब दिए आगे बढ़ा देते हैं ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी कमिश्नर ने बैठक में समय सीमा पत्रों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी समय सीमा के पत्रों का अधिकारी गण समय पर जवाब देना सुनिश्चित करें कमिश्नर ने 100

दिवस से अधिक के सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की एवं महिला एवं बाल विकास विभाग गजस्व विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग स्वास्थ्य विभाग गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहकारिता विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं

अन्य विभाग की बहुत अधिक संख्या में निराकरण के अभाव में लंबित शिकायतों पर नागजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रत्यक्ष में शिकायतकर्ताओं से संपर्क करें और उनकी शिकायतों का निराकरण करें एवं संतुष्टि पूर्वक शिकायत बंद करवाएं कमिश्नर ने लोकसेवा गारंटी के तहत प्राप्त

आवेदनों का भी समय सीमा में लत्रित निराकरण करने के निर्देश दिए कमिश्नर ने प्रभारी सचिव द्वारा विभिन्न विभागों से मांगी गई रिपोर्ट की समीक्षा की और सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभारी सचिव द्वारा मांगी गई रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि समय-समय पर जनप्रतिनिधियों से जो शिकायत या निर्माण कार्य की मांग की जाती है उसका परीक्षण कर निर्माण कार्य एवं शिकायतों का निराकरण किया जाए उन्होंने कहा कि जो निर्माण कार्य या शिकायत शासन स्तर से संबंधित है उनमें उनके हस्ताक्षर से विभागीय सचिव को पत्र प्रेषित किए जाएं समय सीमा की बैठक में कमिश्नर ने मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित मउमंज में विभिन्न शासकीय कार्यालयों के निर्माण के लिए शशि आंबट, मउमंज में सर्किट हाउस निर्माण, सिंगौरीली में

बाईपास निर्माण, सरई में 10 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण कार्य मैहर में नवोदय विद्यालय का निर्माण कार्य शामिल थे कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जिन निर्माण कार्य के लिए शासन स्तर पर पत्र प्रेषित किए जाने हैं इन्हें पत्र प्रेषित किए जाएं, जहां बजट आवंटन की या भूमि की आवश्यकता है वहां आवंटन और भूमि भी प्राथमिकता से प्राप्त कर ली जाए कमिश्नर ने सेवा संकल्प अभियान में सभी विभाग को बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए और कहा कि इस अभियान के तहत जिन विभागों ने उत्कृष्ट कार्य किया है वह अपने उत्कृष्ट कार्य से शासन को अनिवार्य रूप से अवगत कराएं संभागीय समय सीमा की बैठक में संयुक्त आयुक्त वीरेंद्र पटेल, उपायुक्त गजस्व एल एल अहिरवार डिप्टी कमिश्नर दिव्या त्रिपाठी सहित सभी संबंधित विभाग के संभागीय अधिकारी गण उपस्थित थे।

साहू बस्ती और रानी तालाब रोड में चला आरआरआर कलेक्शन ड्राइव, घरों से जुटाई उपयोगी अनुपयोगी सामग्री



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर पालिका निगम रीवा द्वारा मंगलवार को आरआरआर कलेक्शन ड्राइव आयोजित किया गया। वार्ड क्रमांक 21 की साहू बस्ती और वार्ड क्रमांक 40 के रानी तालाब रोड क्षेत्र में नगर निगम की स्वच्छता टीम ने घर-घर पहुंचकर

नागरिकों से संपर्क किया अभियान के दौरान टीम ने नागरिकों को आरआरआर सेंटर (रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल) की पहल के बारे में जानकारी दी नागरिकों को बताया गया कि घरों में कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी उनके लिए उपयोगिता समाप्त हो चुकी होती है लेकिन वही सामान किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ सकता है ऐसे सामान को कचरे में फेंकने के बजाय

आरआरआर सेंटर तक पहुंचाकर उसका दोबारा उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है स्वच्छता टीम ने घर-घर जाकर ऐसी अतिरिक्त और अनुपयोगी सामग्री एकत्रित की जिसका पुनः उपयोग संभव है सामग्री को नगर निगम के आरआरआर कलेक्शन वाहन के माध्यम से संग्रहित किया गया इस दौरान नागरिकों को घर में उपयोग योग्य अनुपयोगी वस्तुओं को अलग रखने और उन्हें कलेक्शन वाहन अथवा आरआरआर सेंटर

तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया नगर निगम की टीम ने नागरिकों से अपील की कि वे घरों में ऐसी वस्तुओं को अलग रखें जिनकी वर्तमान में उन्हें आवश्यकता नहीं है लेकिन उनका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है निगम ने आरआरआर पहल में सक्रिय सहभागिता करने और उपयोग योग्य सामग्री को कलेक्शन वाहन या आरआरआर सेंटर तक पहुंचाने की अपील की।



सांस फूलने पर मिर्गी की दवा देने का आरोप, बेटे को लेकर कलेक्टर के पास पहुंची महिला डॉक्टर ने कहा- आरोप निराधार



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। बेटे के इलाज को लेकर एक महिला सोमवार देर शाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पास शिकायत लेकर पहुंची महिला ने डॉक्टर वीरभान सिंह पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि बच्चे को सांस फूलने को शिकायत थी लेकिन जांच के बाद

उसे मिर्गी की दवा लिखी गई महिला ने डॉक्टर के क्लिनिक से जुड़ा एक वीडियो भी कलेक्टर को सौंपा शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय (एसजीएमएच) के अधीक्षक को बच्चे का उचित इलाज कराने के निर्देश दिए साथ ही मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही सांस फूलने की शिकायत पर डॉक्टर से कराया इलाज महिला के अनुसार बच्चे को सांस फूलने की परेशानी हो रही थी इसी समस्या को लेकर वह डॉक्टर के पास गई थी आरोप है कि जांच के बाद डॉक्टर ने बच्चे को मिर्गी की दवा लिख दी महिला ने बताया कि बच्चे को पहले एसजीएमएच में भी दिखाया गया था जहां उसकी ईसीजी रिपोर्ट सामान्य आने की बात कही गई थी महिला का दावा है कि इसके बाद भी बच्चे का मिर्गी संबंधी उपचार बताया

गया। दोबारा डॉक्टर के पास जाने पर बच्चे की एमआरआई कराने की सलाह दी गई इलाज में करीब 2500 रुपए खर्च होने का दावा महिला ने इलाज के दौरान करीब 2500 रुपए खर्च होने की बात कही उसके अनुसार दो बार करीब 600-600 रुपए फीस ली गई, जबकि लगभग 1500 रुपए की दवाएं लिखी गई महिला ने डॉक्टर के क्लिनिक का एक वीडियो भी कलेक्टर को सौंपा और उसमें डॉक्टर द्वारा मीडिया को लेकर टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया डॉक्टर ने आरोपों को बताया निराधार डॉक्टर वीरभान सिंह ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया उनका कहना है कि बच्चे के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है डॉक्टर ने कहा कि मामले की जांच होने पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी फिलहाल कलेक्टर के निर्देश पर एसजीएमएच में बच्चे के इलाज और मामले की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को दिए निर्देश

सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के साथ जन जागरूकता अभियान भी चलाएं : मुख्यमंत्री

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सेवा संकल्प अभियान को उच्च प्राथमिकता देते हुए इसकी सभी गतिविधियां भलीभांति करें अभियान में अब तक सभी जिलों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है अभियान के तहत 3 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्र और 4 अक्टूबर को शहरी क्षेत्र में सेवा सेतु शिविर लगाए जाएंगे इसके लिए हितग्राहियों का चयन करके उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभांनित करें। शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण करके उनकी जानकारी



पोर्टल में दर्ज कराएं मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से सेवा ज्योति यात्रा शुरू होगी, जिसका जिला मुख्यालय में समापन

होगा समापन स्थल पर सभा का आयोजन करें सेवा ज्योति को जिला मुख्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर स्थापित करने की भी व्यवस्था करें।

सेवा ज्योति यात्रा में हितग्राहियों की भी भागीदारी सुनिश्चित करें जिला स्तरीय कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वचुंअली माध्यम से संबोधित करेंगे इसमें विकसित भारत की शपथ भी ली जाएगी सेवा संकल्प अभियान की गतिविधियों के फोटो, वीडियो और रील्स अच्छी गुणवत्ता के बनवाएं तथा पोर्टल पर अपलोड करवाएं सेवा की कहानियों में भी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के विरुद्ध हर जिले में प्रभावी अभियान चलाएं नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ नशामुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाएं भूलवश नशे की गिरफ्त में आ गए

युवाओं को नशामुक्ति केन्द्र के माध्यम से पुनर्वास के प्रयास करें जिला स्तरीय एनर्काई समिति की हर माह अनिवार्य रूप से बैठक करके पोर्टल पर कार्यवाही विवरण अपलोड करें नशे का निराकरण कारोबार करने वाले अपराधियों के सम्पत्ति की जब्ती की भी कार्रवाई करें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशे के विरुद्ध निगरानी बढ़ाएं बैठक में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा के संबंध में की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगम बस सेवा के लिए सभी जिलों में बस डिपो और बस टर्मिनल की व्यवस्था कराएं यह बस सेवा बस अपरेटर्स के सहयोग से संचालित की जाएगी।